MR. DEPUTY CHAIRMAN: You are correct. ...*(Interruptions)*... I said that. ...*(Interruptions)*... No, no. ...*(Interruptions)*... Nareshji. ...*(Interruptions)*... Nareshji, yes, I said that. At that point of time, it did not come to my mind that Statutory Resolution is listed before Short Duration Discussion. It did not come to my mind. ...*(Interruptions)*... That is the point.

श्री नरेश अग्रवालः माननीय उपसभापति जी, सवेरे सबके माइंड में था, हम लोगों ने पूरा एजेंडा देखा था और चेयरमैन साहब ने कहा था कि इसको पास करा दीजिए, फिर ढाई बजे से Short Duration Discussion के लिए कहा था। ...**(व्यवधान)**... हमसे Short Duration Discussion 2.30 बजे लेने के लिए कहा गया था, अब 3.05 हो गए हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापतिः लेकिन ऐसा क्यों हो गया? ...**(व्यवधान)**...

श्री नरेश अग्रवालः हमने कहा कि अगर पास कराना है तो चलिए हो जाने दीजिए। ...**(व्यवधान)**... लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि बिल लिया जाएगा। ...**(व्यवधान)**...

श्री विजय गोयलः अगर आपकी इतनी ज़िद है, तो इसके बाद आप नाबार्ड से संबंधित बिल भी पास करा दें। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN : All right. मंत्री जी, बैठिए। No, no. ...**(व्यवधान)**... आप सुनिए। Okay. Now, listen. We will take up Short Duration Discussion first. Time allotted for Short Duration Discussion is two hours thirty minutes because time is restricted to that. After that, we will take up the Statutory Resolutions. Okay. Agreed. Now, Short Duration Discussion.

SHRI NEERAJ SHEKHAR (Uttar Pradesh): Sir, after that, will we take up the NBARD Bill? ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Now, I will take up the Short Duration Discussion first, and after that, we will take up Statutory Resolutions.

SHORT DURATION DISCUSSION

Excessively high levels of air pollution in Delhi

श्री नरेश अग्रवाल (उत्तर प्रदेश)ः माननीय उपसभापति जी, बहुत दिनों के बाद आज Short Duration Discussion पर हमें कुछ कहने का मौका मिल रहा है, लेकिन जो सदन की एक परम्परा थी, माननीय उपसभापति जी एवं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, वह परम्परा थी कि हर सप्ताह में एक Calling Attention और दो Short Duration Discussions लिए जाएंगे, वह परम्परा टूट रही है ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापतिः इसे आप सुबह चेयरमैन साहब के सामने discussion के समय बोलिए।

श्री नरेश अग्रवालः हम बोलते हैं, लेकिन आप चुप रहते हैं। यही मुश्किल है। हमने बोला लेकिन आप चुप हो गए। ...(**व्यवधान**)... आप भी बोलिए। जो एक परम्परा थी, वह परम्परा कम-से-कम कायम रहनी चाहिए, क्योंकि बहुत important issue हमारे सामने हैं। हम चाहते हैं कि देश से जुड़े issues का कुछ समाधान निकले। हमारा काम खाली यहां आलोचना करना नहीं है, हम सुझाव भी देंगे।

श्री उपसभापतिः यहां सरकारी Business भी चलना है और discussion भी होना है। दोनों काम करने हैं, ...(**व्यवधान**)... by cooperation. We should cooperate.

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल)ः नरेश जी, आपकी breaking news बहुत आती हैं। ...(**व्यवधान**)...

SHRI JAIRAM RAMESH (Karnataka): Sir, how much time has been allotted for the Short Duration Discussion?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Two hours thirty minutes.

SHRI JAIRAM RAMESH: And how much time will the Minister take to give his reply? Will he take two-and-a-half hours?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Minister's reply will be in less than thirty minutes. The Minister will not be given more than thirty minutes.

श्री नरेश अग्रवालः माननीय उपसभापति जी, आज पर्यावरण की जो हालत है, उसे लेकर पूरा विश्व चिंतित है। ऐसा नहीं कि खाली हिन्दुस्तान ही चिंतित है, पूरा विश्व चिंतित है। अगर हर फिगर में हम सबसे टॉप पर आते हैं, तो हमें और ज्यादा चिंता होनी चाहिए। दिसम्बर का महीना है। आप देख लीजिए किं ठड पड़ रही है। जब सुबह मैं टहलने जा रहा था तो मेरा Security वाला बोला कि साहब, आप मत ठहलिए। कोहरा है, पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा है। इस पॉल्यूशन में ठहलने से ज्यादा नुकसान होगा। अगर राजधानी में, जहां देश की सरकार रहती है, जिसे सारे लेन-देन करने हैं, अगर राजधानी की स्थिति ऐसी रहेगी तो विश्व में हमारी क्या image बनेगी? श्रीलंका की क्रिकेट टीम जब यहां खेलने आई, दिल्ली में क्रिकेट मैच था, उनके प्लेयर्स मास्क लगाकर खेले, जिन्हें पूरे विश्व में टेलीविज़न पर देखा गया, क्या वह हमारे देश के लिए बहुत अच्छा रहा? अमेरिका ने दिल्ली आने वाली अपनी Airlines कैंसिल कर दीं तथा यूरोप और अमेरिका में Advisory जारी की गई कि दिल्ली की पॉल्यूशन की स्थिति बहुत खराब है, आप भारतवर्ष मत जाइए - क्या वह हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ?

आज विश्व के जो पाँच सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटीज़ हैं, उनमें एक नम्बर पर दिल्ली, दूसरे नम्बर पर बीज़िंग, तीसरे नम्बर पर सीटल, चौथे नम्बर पर एक्सपोसिटी और पांचवें नम्बर पर कायरो है। ...(**व्यवधान**)... नहीं, पाकिस्तान का कोई सिटी नहीं है। जो पाँच विश्व के सबसे पॉल्यूटेड शहर हैं, उनमें दिल्ली का नाम है। पर्यावरण मंत्री जी, आप भी दिल्ली के रहने वाले हैं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री

[श्री नरेश अग्रवाल]

जी, आप भी दिल्ली के रहने वाले हैं। हमें देखना होगा कि स्थिति बिगड़ क्यों रही है? इस पर हम लोगों ने अब तक क्या किया? हर साल जब सर्दी आती है, पॉल्यूशन की स्थिति खराब होती है लेकिन दोष किसानों पर मढ़ दिया जाता है कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के किसान जो पराली जलाते हैं, उसके कारण दिल्ली में प्रदूषण है, लेकिन क्या यह सही स्थिति है? वे तो सैंकड़ों सालों से जलाते चले आ रहे हैं। क्या सैंकड़ों साल पहले दिल्ली कभी इतनी पॉल्यूटेड हुई? पिछले तीन-चार साल से दिल्ली इतनी पॉल्यूटेड क्यों होने लगी? क्या ऐसा किसानों की वजह से हुआ? सरकार ने तमाम घोषणाएँ कीं। हरियाणा सरकार ने कहा कि हम पराली का compensation देंगे। सब लोग कहते तो हैं, लेकिन होता क्या है? मैं आज अख़बार में पढ़ रहा था कि पर्यावरण मंत्रालय ने यह कहा है कि हम 12-सूत्री कार्यक्रम बना रहे हैं। जब मैंने अख़बार में उस 12-सूत्री कार्यक्रम को पढ़ा, तो मुझे हँसी आ गई। उसमें लिखा था - "मैं राज्य सरकार को यह निर्देश दूंगा, मैं फॉरेस्ट विभाग को यह निर्देश दूंगा।" केवल निर्देश देने से अगर पॉल्यूशन खत्म हो जाए, तो फिर निर्देश देने में कितना समय लगता है? हमें आप दे दो, हम यहीं पर से वे निर्देश पढ़ दें। शायद वह अख़बार में न छप पाए, लेकिन यहाँ तो पूरा विश्व देख रहा है, सभी लोग टीवी देख रहे हैं। अगर आप केन्द्र की सरकार से पूछिए, तो सुनने को मिलता है कि दिल्ली सरकार कुछ नहीं कर रही है। जब अमेरिका के राष्ट्रपति बीज़िंग की यात्रा पर जा रहे थे, तो चाइना की सरकार ने पॉल्यूशन की खराब स्थिति के लिए वहाँ पर आर्टिफिशियल पानी गिराया और अमेरिका के राष्ट्रपति वहाँ तब गए, जब वहाँ पॉल्यूशन खत्म हो गया।

हमने एनजीटी बना दिया। यह सोचा गया था कि एनजीटी बन जाएगा, तो सारा पर्यावरण एकदम ठीक हो जाएगा। वे जज रिटायर हो गए। उन पर खुद ही आरोप लग गए थे। किसने लगाए, यह मैं नहीं बोलूंगा। श्रीमन्, उन्होंने तुगलकी फरमान जारी करने शुरू कर दिए। उनके फरमान के बाद अगर किसान अपने खेत से एक छटांक भी मिट्टी लेना चाहे, जिससे उसे अपने घर की लिपाई करनी है, क्योंकि गाँव में कच्चे मकान हैं, तो वह मिट्टी नहीं खोद सकता, पुलिस वाला उसको बन्द कर देगा। कोई आदमी अपने आप उन पेड़ों को भी नहीं काट सकता, जो प्रतिबंधित नहीं हैं। एनजीटी ने दिल्ली में पॉल्यूशन ठीक करने का टैक्स लगाया। उसका करीब 800 करोड़ रुपया आपके पास जमा है, वह रुपया क्या कर रहा है? पर्यावरण मंत्रालय कहता है कि वह दिल्ली सरकार के अधीन है, उसको दिल्ली सरकार देखेगी और दिल्ली सरकार कहती है कि हमारे पास कोई अधिकार नहीं है, सब अधिकार भारत सरकार के पास हैं। ये सब दोनों की लड़ाई के बीच में पड़ा हुआ है। अगर हम इन चीज़ों पर नहीं जाएँगे और सत्यता पर नहीं जाएँगे, तो पॉल्यूशन की बिगड़ती स्थिति लोगों को लंग्स का रोगी बना रही है, हृदय का रोगी बना रही है, साँस का रोगी बना रही है, कैंसर का रोगी बना रही है और आँखें भी खराब कर रही है। जब हम अपनी आँख डा. टिटियाल को दिखाने गए, तो उन्होंने कहा कि पॉल्यूशन के कारण ऐसा है। हमारे पुराने संसदीय कार्य मंत्री अब कैबिनेट मिनिस्टर हो गए हैं, पहले ये हमारी आँखें दिखवा देते थे, लेकिन अब ये चले गए, तो हमें खुद ही दिखानी पड़ रही है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Not only eyes, but also the chest.

श्री नरेश अग्रवालः उसके कारण चेस्ट प्रॉब्लम भी होती है और आइज़ प्रॉब्लम भी होती है। वे कहने लगे कि यह पॉल्यूशन की वजह से है। यह बताइए कि आम लोगों की क्या हालत है? दिल्ली में जिन-जिन जगहों पर आपके इंटर-स्टेट बस स्टैंड हैं, वे सारी जगहें, जहाँ इंटर-स्टेट बसें आकर खड़ी होती हैं, वहाँ की क्या हालत है? मैं नाम लिखकर नहीं लाया हूं, लेकिन दिल्ली में ऐसी तमाम जगहें हैं, जहाँ पर बस अड्डे हैं, वहाँ पर प्रदूषण की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। वह पराली के कारण खराब नहीं है, बल्कि बसों के कारण है। आज यहाँ कितने व्हिकल्स निकल रहे हैं? हमें यही नहीं मालूम कि दिल्ली में या इंडिया में कितने व्हिकल्स प्रतिदिन निकल रहे हैं। उन पर रोक लगाने की कोई व्यवस्था नहीं है। क्या आपको मालूम है कि सिंगापुर में आप दूसरी गाड़ी तब तक नहीं खरीद सकते, जब तक सरकार की परमिशन न मिल जाए? आपने ऑड-ईवन व्यवस्था चला दी और उस ऑड-ईवर के कारण लोगों ने यह सोचकर और एक्स्ट्रा गाड़ियाँ खरीद लीं और एक ऑड नम्बर की गाड़ी रख लो और एक ईवन नम्बर की गाड़ी रख लो। इसका यह कोई साल्यूशन नहीं है। हमको यह सब देखना पड़ेगा। अगर हमने नहीं देखा, तो केवल यह न हो जाए कि सदन में इस पर चर्चा हुई थी। अगर चर्चा के अलावा सत्यता रहेगी, तो ज्यादा अच्छा है। अब तो यह होता है कि राजस्थान में बाढ़ आ गई। एकदम हम लोगों को हंसी आती है कि राजस्थान के उन इलाकों में जहां दस साल से पानी नहीं गिरता था, जहां लोग पानी नहीं देखते थे, दुबई तक तो पानी गिरने लगा। हमरे यहां बुंदेलखंड जहां सूखा ही सूखा पड़ता था, वहां अच्छा पानी गिरने लगा। यह पर्यावरण का चेंज नहीं है तो क्या है? वन लगाने की बात है, सब जानते हैं कि पेड़ की कटाई से पर्यावरण की स्थिति बहुत खराब हुई है।

[**उपसभाध्यक्ष, (श्री भुवनेश्वर कालिता)** *पीठासीन हुए]*

सब वैज्ञानिक इस बात को कहते भी हैं। यह हुआ कि जितनी लैंड है, उसका 33 परसेंट फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए। World wild life fund ने उत्तर प्रदेश में तीन बार इतने पेड़ लगा दिए कि उत्तर प्रदेश में कहीं जमीन बची ही नहीं। वर्ल्ड बैंक से जब लोन लिया तो तीन बार इतने पेड़ लगा दिए कि हर तीन फीट पर एक पेड़ लग गया। लेकिन उत्तर प्रदेश में 12 परसेंट से ऊपर वन नहीं हैं। उत्तरांचल हटने के बाद तो और बुरी हालत हो गई। तो क्या हमने पॉलिसी बनाई कि फॉरेस्ट एरिया कैसे बढ़ाएं? मैं तो कहता हूं कि अभी भी तमाम नंगे पहाड़ खड़े हुए हैं। आप बद्रीनाथ साइड चले जाइए, एक पेड़ आपको नहीं मिलेगा, केदारनाथ की कुछ ऊंचाई पर जाइए वहां भी नहीं है, गंगोत्री में तो आपको पेड़ ही नहीं मिलेगा। उन पहाड़ों के लिए जब हमारे से जर्मन और फ्रांस के एक्सपर्ट कहते हैं कि आप हमको दे दीजिए, हम वहां पेड़ लगा देंगे, आपके पहाड़ पूरे हरे कर देंगे, तो क्या दिक्कत है आपको? अब जब डब्ल्यू.टी.ओ. लागू हो गया, एफ.डी.आई. दे ही रही हैं, आज बुलेट ट्रेन का ठेका जापान को दे सकते हैं तो क्या पेड़ लगाने का काम नहीं दे सकते उन लोगों को? जब हम फेल हो गए, हमारे एन.जी.ओ. फेल हो गए, आज इतने एन.जी.ओ. हैं कि आप लिस्ट निकाल लीजिए तो ताज्जुब मान जाएंगे कि कितने एन.जी.ओज़. इस देश में पेड़ लगा रहे हैं और पर्यावरण ठीक कर रहे हैं। कितना पैसा उनको मिल रहा है और क्या पर्यावरण ठीक हुआ है? दिल्ली के क्लब में शाम को पर्यावरण ठीक करते हैं और टी.वी. पर बैठ कर हिन्दुस्तान भर को उपदेश देते हैं। मैं कुछ बोल देता हूं तो बुरा लग जाता है। मैं देखता हूं कि कुछ लोग रोज़ टी.वी. पर बैठ जाएंगे डिस्कशन के लिए। वहां इतने उपदेश देंगे कि उनसे

[श्री नरेश अग्रवाल]

बड़ा ज्ञाता ही कोई नहीं है। आप लोग भी सुनते होंगे उनके उपदेश। यह टी.वी. वालों ने नया ट्रेंड चलाया है कि किसी को बिठाना हो, अगर हर्षवर्धन जी पर हम एक टिप्पणी कर दें तो शाम तक देखें और कल तक तो हमारे ऊपर कितनी टिप्पणियां होंगी कि हमने क्या कहा? हमने तो इतना ही कहा कि पाकिस्तान ने उनको फांसी की सजा दी, क्यों दी फांसी की सजा? हम इंटरनेशनल कोर्ट में लड़ रहे हैं, हम अपने यहां आतंकियों को क्यों पाल रहे हैं? 12 साल में कसाब को सजा मिलेगी, अफ़ज़ल गुरु जिसने पार्लियामेंट पर अटैक किया था, उसको 10 साल बात सजा मिली। सजा भी एक दिन रात में रोक दी गई। हम तो उन आतंकवादियों को पाल रहे हैं, लज़ीज़ कबाब खिला रहे हैं, बिरयानी खिला रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की जेलों में जो हमारे लोग बंद हैं, जाधव जैसे और भी सैकड़ों लोग बंद हैं, उनकी जब यह हालत हो रही है तो क्या कर रहे हैं? तो अतीत में डर कर हम लोगों को बैठ गया कि हम कोई निर्णय लेंगे तो आलोचना हो जाएगी, मीडिया आलोचना करना शुरू कर देगा। हम आलोचना के डर से कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं। इस निर्णय की स्थिति ने हमको बहुत खराब स्थिति में पहुंचा दिया है।

मैं एक बात और कह दूं कि यह जो हम पोलिटिकल लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ जांच का नया ट्रेंड शुरू किया है, मैं आज ही हिमाचल प्रदेश के नए चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि पिछली सरकार के छः महीने के कार्यों की समीक्षा की जाएगी। हमारे उत्तर प्रदेश में जितने अच्छे काम हुए थे, सब पर जांच बैठ गई। तो अगर हमारा काम सरकार बदलने के तुरन्त बाद जांच बिठाना ही हो गया तो फिर कोई बाबू, आई.ए.एस. कुछ काम नहीं करेंगे। मंत्री जी जब तक फाइल पर नहीं लिखेंगे, हमारा आपका दम नहीं कि उसको ओवर रूल कर दें।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवेनश्वर कालिता)ः नरेश जी, आप समाप्त कीजिए आपका टाइम खत्म हो गया है। 12 मिनट हो गये, आपका टाइम 11 मिनट था।

श्री नरेश अग्रवालः आप तो बड़े दिल वाले हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवेनश्वर कालिता)ः इसलिए मैं 12 मिनट तक रुका।

श्री नरेश अग्रवालः माननीय मंत्री जी, यह ठीक है कि हम कोयले से चलने वाले उद्योगों को बंद कर रहे हैं, लेकिन आप उसका विकल्प भी तो बताइए। यह कहा गया कि हमने दिल्ली से निकाल दिया, वह सब आपने नहीं निकाला, कोर्ट ने आदेश किया, एनजीटी ने तमाम आदेश कर दिए। पेपर मिल वालों को आपने मना कर दिया, लेकिन अगर alternatively सब इंडस्ट्रीज़ को बंद करते चले गए, तो वह भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं होगी। आज नदियों के प्रदूषण की क्या हालत है? गंगा पर प्रदूषण समाप्त करने के लिए कितना रुपया खर्च हो गया? हम लोग तो गंगा के पास ही रहने वाले हैं - "हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है" - हमारे हरदोई के पड़ोस से तो गंगा निकलकर गयी है, कन्नौज हरदोई का बॉर्डर है। गंगा का प्रदूषण केवल चिताएं जलाने से नहीं है, गंगा का प्रदूषण, आपकी फैक्ट्रियों ने जो कैमिकल डाल दिया है, उसकी वजह से है। वहां मछलियां मर गयीं, कछुए मर

गए। यही pollution को खाते थे, गंगा को clean रखते थे, लेकिन हमारे इस pollution ने हमारी उस स्थिति को खराब कर दिया। जिस शहर की नदी गंदी हो, वह शहर सबसे गंदा होता है। आप चलकर यमुना का हाल देख लीजिए। हम जब कभी ट्रेन से आते हैं और यमुना नदी के ऊपर से ट्रेन निकलती है तो वहां बिल्कुल काला पानी है, उसमें से बदबू अलग आती है, पता नहीं कैसे गरीब लोग वहां रहते हैं! जब इतनी काली हमारी दिल्ली की यमुना है, तो यहां पर प्रदूषण की स्थिति क्या होगी, दिल्ली की क्या हालत होगी? आपने आज निकाला कि हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम को electric system करने जा रहे हैं। आप ऐसा कब कराएंगे? यहां पर Urban Development Minister भी बैठे हुए हैं। मैं कहता हूं कि ठीक है, alternate निकालिए, किसी तरह से pollution दूर हो। दस साल पुरानी गाड़ियों के संबंध में आदेश हुआ था, फिर वह रुक गया। यह सही है कि बहुत पुरानी गाड़ी बहुत अधिक pollution फैलाती है। आप उन गाड़ियों को खत्म ही करिए, ऐसा न हो कि आपकी दिल्ली की खराब गाड़ियां हमारे उत्तर प्रदेश में पहुंच जाएं, क्योंकि दिल्ली में बैन हुईं और उत्तर प्रदेश में खुली रहीं तो सब गाड़ियां दिल्ली से उत्तर प्रदेश में पहुंच जाएंगी, हरियाणा में पहुंच जाएंगी और वहां pollution फैलाएंगी। आप कोई एक नीति बनाइए, कोई ऐसा विकल्प बनाइए कि हिन्दुस्तान की pollution की स्थिति सुधरे। हमारे यूपी में लखनऊ, गाजियाबाद और नोएडा में तो दिल्ली से ज्यादा pollution है, वहां की स्थिति तो और ज्यादा खराब है। तो हर्ष वर्धन जी, हर्ष के साथ, खुशी के साथ आप कोई बड़ा निर्णय लीजिए। आपको उसमें क्या दिक्कत है? आप इतनी बड़ी majority के बाद अगर निर्णय लेकर उसको ठीक न कर पाएं, तो यह ठीक नहीं है। आप तो डॉक्टर रहे हैं, आप तो नब्ज़ पकड़कर जान जाते होंगे कि क्या समस्या है। हम लोग तो राजनैतिक डॉक्टर हैं, हमारे पास जब कोई गांव वाला आता है तो हम दूर से ही जान जाते हैं कि यह किस काम के लिए आ रहा है। उसी तरह से आप भी डॉक्टर हैं। आप पर्यावरण के डॉक्टर बन जाइए और इसको ठीक करिए, ...(**समय की घंटी**)... यही हमारा आपसे अनुरोध है। हम आलोचना करने नहीं आए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि प्रदूषण ठीक हो और हम सब भी एक अच्छी जिंदगी जी सकें। सर, यूरोप में अगर ढाई एमजी से ऊपर प्रदूषण पहुंच जाए तो हल्ला मच जाएगा, लेकिन हमारे यहां ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको ठीक कीजिए, यही हमारा आपसे अनुरोध है, बहुत-बहुत धन्यवाद।

DR. T. SUBBARAMI REDDY (Andhra Pradesh): Sir, the surge in spread of toxic air in Delhi is giving so much trouble that we are also not able to go for walking. I am afraid to walk and putting up weight because of this problem. I must say, according to a recently published study in a Journal of the American Medical Association, the risk is even higher among elderly people, females and result in premature death of elderly. So, it is very dangerous.

The most important thing is to have greenery. Even though New Delhi is having good plantation, still it is not sufficient. The amount of air pollution is going up exponentially. So, we need greenery not only within the city limits or surroundings of city, but also in outskirts, such as Dwarka and beyond this. We need massive plantation. So, I would suggest for consideration of the hon. Minister, Dr. Harsh Vardhan, that plantation has to

[Dr. T. Subbarami Reddy]
be taken up on a massive scale. What we are planting now has to be multiplied ten times in all places. Another most important thing is, there should be coordination between the Governments of Punjab, Haryana and Uttar Pradesh. I am happy, recently, the Central Government appointed a High Level Committee headed by the Principal Secretary to the hon. Prime Minister. They are already coordinating between the Chief Secretaries of these three States. It is a good step. But, at the same time, I would also like to say that the National Green Tribunal is also playing a very important role. It has formulated a graded response action plan for combating the air pollution in Delhi. But, it lacks coordination among many stakeholders. There is a news report that the NGT and the SC-mandated Environment Pollution Control Authority (EPCA) do not see eye to eye. It is a very dangerous situation. They must have a good relationship. But, there is a great confusion. I would like to know who is going to do away this confusion and make them work together.

I am happy to know that the Principal Secretary to the hon. Prime Minister has drafted a Twelve Point Draft Action Plan. I would like to know what this Twelve Point Draft Action Plan is. How is it going to achieve the goal? What is the time limit? How is it going to solve the problem of pollution?

Solid waste management is another major reason of pollution. The Municipal Corporations of Delhi are not properly doing solid waste management. Last week, I had raised this point during the Zero Hour also. But, there is no response till now. Improper and poor solid waste management is causing a lot of pollution.

Vehicular pollution is another major problem in Delhi. Of course, in modern life the cars and transportation are very important. But, the cars are growing at a rapid pace in the city. It is also very important to see how best we can limit the cars on the roads by providing alternative public transport system. The increasing number of cars may, perhaps, be controlled by providing more and more air-conditioned buses and by encouraging the employees to use the public transport system instead of using their individual cars for commuting. Of course, it is difficult to implement. But, we will have to apply our mind as to how best we can do it.

The pollution in the Ganges and the Yamuna is yet another major cause of concern. I was very happy that the NDA Government was aggressively promising to clean the rivers, particularly the Ganges and the Yamuna. They were trying to get assistance from

the World Bank also for this purpose. But we still find — as Shri Naresh Agrawal was telling about the Ganges and Yamuna — that nothing much has improved. So, I would like to know from the Government as to what their action plan in this regard is. How are they going to improve the condition of the Ganges and the Yamuna?

You have also to improve the public transport by integrating the Metro Rail and the Delhi Transport Corporation services through Journey Planner Apps and linking ticketing in DTC buses, the State Transport Cluster Buses and trains. It is very important. If you improve these facilities, then, people would not use their individual cars, scooters, and motorcycles.

You have also to ensure the completion of the Eastern and the Western Peripheral Expressways within the target dates.

One of the action plans is to encourage electric vehicles, including prioritizing their use for public transport and providing last-minute connectivity. Of course, electrifying cars may take some more time. But, at least, electric buses and other public transport systems may be provided.

In conclusion, I would like to reiterate that the number of increasing vehicles on the roads, lack of green cover, crop residue burning by the farmers in the neighbouring States are the major sources of pollution. Therefore, the Governments of Punjab, Haryana and Uttar Pradesh should frame plans to curb and monitor the stubble burning. The Ministry of Environment must develop a dashboard of all red category pollution units and ensure that all these units have installed certified pollution meters on the premises. I have already emphasized on the need of solid waste management in an effective manner. There should always be focus on hundred per cent solid waste management. The Municipal Corporations of Delhi play a very important role in this regard. Then, a High Level Task Force, headed by the Principal Secretary, had been constituted. I would again like to call upon him and also the Government as to what the Twelve Point Draft Action Plan is. We would like to know, as early as possible, what the 12-Point Action Plan is, how it is going to solve the problem of air pollution and what is the timeframe, etc. With these words, i pray to God that the prestigious city of India, the Capital, New Delhi, becomes pollution free and remains a prestigious city. We all must work together to see that the Delhi city becomes a clean city. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Thank you, Dr. Reddy. The next speaker is Dr. Vinay P. Sahasrabuddhe.

डा. विनय पी. सहस्त्रबुद्धे (महाराष्ट्र): उपसभाध्यक्ष जी, दिल्ली के प्रदूषण के विषय पर सदन में चर्चा चल रही है। मैं मानता हूं कि यह बड़ी प्रासंगिक चर्चा है और प्रदूषण का विषय केवल कहने का विषय नहीं है। इस पर लंबा भाषण देना या उपदेश करना तो आसान है, मगर यह हम सब की जिंदगी से जुड़ा एक विषय है, इसलिए मैं मानता हूं कि यह हमारे क्रियान्वयन में भी झलकना चाहिए। Our own life-style also has to be very environment-friendly. If that is not happening, all sermons about environment and ecological considerations, I am afraid, are going to be sounding very hollow. महोदय, यह एक अल्पकालीन चर्चा है, मगर प्रश्न दीर्घकालीन है। यह कोई विगत तीन-साढ़े तीन सालों में निर्माण हुआ प्रश्न नहीं है और मैं मानता हूं कि केवल सरकार के दरवाजे पर आकर इस बारे में दुहाई दें और समस्या के समाधान की बात करें, यह भी शायद बहुत जिम्मेदाराना व्यवहार नहीं होगा, जितना कि हम सब मिलकर इस विषय में सोचें और क्रियान्वयन के धरातल पर अपने आचरण में कोई बंधन लाएं या कुछ-न-कुछ करें।

महोदय, अच्छी बात यह है कि विगत तीन सालों से आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, जो सरकार केन्द्र में काम कर रही है, उसने पर्यावरण के विषय पर कुल मिलाकर एक व्यापक सोच बनायी है। हमारे प्रधान मंत्री, जब गुजरात के मुख्य मंत्री थे, तब भी उन्होंने पर्यावरण के विषय पर कुछ लेखन किया था और नीतिगत बातें रखी थीं और एक प्रतिबद्धता के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। We are committed to the protection of environment और इसलिए इसी सरकार ने स्वच्छ भारत जैसे कार्यक्रम को हाथ में लिया है, जोकि पर्यावरण के लिए भी है। इस के बाकी सामाजिक और आर्थिक पहलू भी हैं, मगर हम पर्यावरण के पहले की भी अनदेखी नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि इस सरकार की सोच एक मूलभूत दिशा को इंगित करती है। महोदय, हमारे देश में वर्षों से इस बारे में डिबेट हो रही है। अब कुछ लोगों ने यह भी कहा कि ecology एक luxury है और यह एक वातावरण बनाया गया था कि either you can protect environment or you can promote industry, मतलब उद्योग को बढ़ावा देना और पर्यावरण की रक्षा में कोई द्वैत है, ऐसा वातावरण बनाने की भी कोशिशें होती रही हैं। महोदय, हमारी सरकार की यह नीति है कि विकास और पर्यावरण हाथ-में-हाथ डालकर चल सकते हैं। अतः पर्यावरण का भी विकास होना चाहिए और विकास का पर्यावरण भी बरकरार रहना चाहिए। मैं मानता हूं कि इस मूलभूत बिंदु के बारे में हम सभी को मिलकर सोचना चाहिए। तीसरी बात, इस सरकार ने पहली बार इस देश में वातावरणीय परिवर्तन या climate change के बारे में पर्यावरण विभाग में ही एक अलग विभाग का निर्माण किया, जो समय की आवश्यकता के अनुरूप था और अपने उत्तरदायित्व को पहचानते हुए इस सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया।

महोदय, कई बार लोगों को लगता है कि नया और अलग क्या हो रहा है? मैं बताना चाहता हूं कि हमारे देश में सोलर एनर्जी के बारे मे काफी समय तक चर्चा चलती रही, मगर सोलर एनर्जी को एक international relations का platform बनाते हुए एक International Solar Alliance के नाम से एक संस्थागत ढांचे के निर्माण के लिए आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी को प्रधान मंत्री बनना

पड़ा, इस वास्तविकता को भी हमें समझना पड़ेगा। उपसभाध्यक्ष जी, हम यह भी जानते हैं कि सरकार में आने से एक साल पहले, वायु प्रदूषण की समस्या कोई कल-परसों से चर्चा में नहीं आयी है, यह समस्या पहले से थी। मगर इस पर कारगर उपाय ढूंढने के लिए देश में पहली बार - और हम सबको यह समझना चाहिए कि National Air Quality Index इस देश में अप्रैल, 2015 में पहली बार बना था, क्योंकि हम हवा, जल, प्रदूषण के बारे में चिंतित हैं, अपने दायित्वों को समझते हैं और कारगर योजना और उपाय करने की दिशा में भी काम करना चाहते हैं।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं यह मानता हूं कि इस सरकार ने कुल मिलाकर तीन विषयों पर बहुत गंभीरता से काम किया है। यह अच्छी बात है कि इस सरकार के चलते तीन अच्छे व्यक्तियों को इस मंत्रालय का कार्यभार मिला। हम यह भी जानते हैं कि इससे पहले, जिन्होंने दायित्व संभाला, वे कैसे-कैसे टैक्स लाए और उनकी कैसी-कैसी चर्चा मीडिया में चलती रही। मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, मगर एक प्रमाणिकता से, कमिटमेंट के आधार पर, पर्यावरण की रक्षा में भी लोग आर्थिक प्रदूषण करते रहे, उससे पूरा बचते हुए, पूरे कमिटमेंट के साथ, प्रतिबद्धता के साथ इस सरकार में बैठे लोगों ने पर्यावरण की रक्षा का काम किया है। मैं तीन बिन्दुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पहला बिंदु अध्ययन करना है। पर्यावरण का विषय ऐसा नहीं है कि मन में बात आई, निष्कर्ष निकाल लिया और आगे बढ़ें। यह नीगित सोच का विषय होता है और इस सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर, जैसे सरकार ने पृथ्वी विज्ञान विभाग ने, Earth Sciences Department ने Scientific Assessment of Delhi Winter Air Quality Crisis, पर 6 से 16 नवंबर के दरम्यान पूरा अध्ययन करके अपने निष्कर्ष निकाले हैं और यह बार-बार होता जाएगा। अर्थ विज्ञान मंत्रालय या पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा इस तरीके का एक प्रयास करना, यह अपने आप में इस दिल्ली शहर के पर्यावरण के संदर्भ में चर्चा के जितने भी सारे बिंदु आते हैं, मैं मानता हूं कि उनके लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है। केवल इतना ही नहीं, उसके पहले भी 2017 के जून महीने में ICMR के द्वारा Effect of Air Pollution on Acute Respiratory System पर एक रिसर्च की गई कि कुल मिलाकर हमारे फेफड़े के स्वास्थ्य की स्थिति क्या बनती है। Indian Council of Medical Research के द्वारा एक रिसर्च की गई। इसके जो निष्कर्ष आए, उन पर यह सरकार silos में काम नहीं करती। इस सरकार में ऐसा कभी नहीं होगा कि बायाँ हाथ क्या करता है, उसका दाएँ हाथ को पता नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है, पर्यावरण मंत्रालय है, ये सारे मंत्रालय मिलकर पर्यावरण की त्रासदी का, इस चुनौती का सामना करने के लिए खुद को, लोगों को और अन्यान्य सरकारों को सन्नद्ध कर रहे हैं।

महोदय, मैं नई तकनीक की बात भी कर सकता हूं। हमारे श्रीमान नितिन गडकरी जी नई-नई प्रतिभाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। यह जो पराली की आती है कि हमारे जो पौधे हैं, जब तक हम उन्हें पराली से नहीं निकालते हैं, जिसको जलाया जाता है, उसके लिए कौन-सी नई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा सकता है? इस पर भी शोध कार्य जारी है। मैं मानता हूं कि किसानों के पास जाकर इसके बारे में भी जन-जागरण होगा। ये जो नये विकल्प सामने आ रहे हैं, मैं मानता हूं कि इसके क्रियान्वयन के धरातल पर भी हम कुछ न कुछ कर पाएंगे।

[डा. विनय पी. सहस्रबुद्धे]

उपसभाध्यक्ष महोदय, जहाँ तक क्रियान्वयन की बात है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि Ministry of Environment and Forest के द्वारा एक Apex Committee और Working Group भी बनाया गया है, जिसमें सारे विभाग इकट्ठे मिलकर काम कर रहे हैं और इस वर्किंग ग्रुप की बैठकें भी निरंतरता से हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि केवल दिसंबर में क्राइसिस होता है, चर्चा होती है, सुर्खियां बनती हैं, विमानों की आवा-जाही में कुछ परिवर्तन होता है कि कुछ क्राइसिस आया है तो चलो, बस उसी के ऊपर चिंता करो। यह ऐसा विषय नहीं है। इस विषय पर साल भर कुछ न कुछ अध्याय होता रहा है और नीतिगत उपाय, संस्थागत उपाय के माध्यम से इस सरकार की इस समस्या को हल करने की एक प्रणाली है।

महोदय, जहाँ पर GRAP का विषय आया, Graded Response Action Plan for Control of Pollution, यह जो GRAP है, इसके बारे में भी एक संस्थागत ढांचा बना है और अभी सारे लोग मिलकर इसके क्रियान्वयन की तरफ ध्यान दे रहे हैं। मैं मानता हूं कि यह भी एक महत्वपूर्ण पहल इस सरकार की ओर से हुई है, जिसकी हमें अनदेखी नहीं करनी चाहिए।

महोदय, सबसे महत्वपूर्ण बात, जिसका जिक्र पूर्व वक्ताओं ने भी किया कि माननीय प्रधान मंत्री के कार्यालय के अंदर, प्रधान मंत्री के जो सचिव हैं, उनकी अध्यक्षता में एक हाई पावर ग्रुप बना है। यह केवल एक या दूसरे मंत्रालय से संबंधित विषय नहीं है, बल्कि पूरी कैबिनेट का इसके ऊपर ध्यान है, इसलिए स्वयं प्रधान मंत्री के नेतृत्व में, जो प्रधान मंत्री कार्यालय है, उस कार्यालय के द्वारा भी इस विषय की समीक्षा निरंतरता से और समय-समय पर, बार-बार करने की एक कवायद शुरू हुई है।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, यद्यपि हमें इसको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सोचना चाहिए, बावजूद इसके, दूध का दूध और पानी का पानी साफ होना चाहिए।

महोदय, हम यह मानते हैं कि दिल्ली के प्रदूषण के बारे में, दिल्ली की हवा के प्रदूषण के बारे में दिल्ली सरकार की भी कोई जिम्मेदारी है। यद्यपि केन्द्र सरकार दिल्ली सरकार के साथ समन्वय बैठाती है। कई बार दिल्ली सरकार ने वायदे किए, आश्वासन दिए, जैसे हेलीकॉप्टर और वाहनों के माध्यम से सड़कों पर पानी फेरा जाएगा, जिसके कारण प्रदूषण को समाप्त करने की या कम-से-कम उसको काबू करने की कवायद की जाएगी, मगर जहां तक मेरी जानकारी है, उस विषय में कुछ हुआ नहीं। किसी को तो दिल्ली सरकार को भी यह कहना चाहिए। यहां पर दिल्ली सरकार के काफी मित्र हैं, जैसा कि ध्यान में आ रहा है, वे भी जरूर बताएं। They can use their good offices to impress upon the minds of the leaders of Delhi Government that they also have to contribute and they also have to shoulder the responsibility.

महोदय, इसके पहले कि मैं अपना भाषण समाप्त करूं, मैं तीन-चार सुझाव देना चाहता हूं। पहली बात यह है, जैसा कई बार जिक्र आता है हरियाणा, उत्तर प्रदेश का, जिसका अभी नरेश जी ने भी जिक्र किया, जो किसानों के द्वारा खेतों को जलाए जाने की प्रक्रिया होती है, उसके कारण प्रदूषण होता है। मैं जानता नहीं कि इसमें कितना तथ्य है? हां, यह 25 परसेंट, 30 परसेंट होता है या

40 परसेंट होता है, जो भी हो, कुछ मात्रा में तो यह होता ही है। मेरा मानना है कि हरियाणा में, उत्तर प्रदेश, पंजाब में, यहां दिल्ली में भी किसानों के अपने संगठन हैं, अच्छे-खासे फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको भी एक बार कभी इकट्ठा बुलाया जाए और उनके साथ मंत्रणा की जाए। अगर किसानों के अंदर भी दिल्ली की समस्या को लेकर जागरूकता का निर्माण करते हैं, तो मैं आश्वस्त हूं कि दिल्ली की समस्या के लिए ये जो आजू-बाजू के किसान हैं, निश्चित रूप से वे सहयोग करने की मुद्रा में आएंगे। दिल्ली में जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं, RWAs हैं, दिल्ली की सरकार का यह दायित्व बनता था कि उनको भी इकट्ठा करती और उनके साथ भी समन्वय करती, उनको भी बताती, यह छोटा-मोटा प्रदूषण होता है, जैसे हम देखते हैं कि जाड़े के मौसम में हम जो हीटर चलाते हैं, उससे भी प्रदूषण बनता है। तो इन सारे विषयों के बारे में भी कुछ न कुछ करने की आवश्यकता है। दिल्ली में लाखों ट्रक्स आते हैं, उनके जो ड्राइवर्स हैं, उनके भी संगठन हैं, ट्रक मालिकों के संगठन हैं। उनके साथ भी समन्वय बैठाते हुए, संपर्क सेतु निर्माण करते हुए बात होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि इस विषय में भी निश्चित रूप में कुछ करने की आवश्यकता है।

एक जो दूसरा बिन्दु है, वह नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल के बारे में है। कई बार, उपसभाध्यक्ष जी, समझ में नहीं आता कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल क्रियान्वयन के लिए ऐसे अक्षम, actions which are non-implementable, ऐसे डिसीज़ंस क्यों देते हैं? अगर ऐसे डिसीज़ंस देते हैं, तो एग्जीक्यूटिव के क्षेत्र में एक दृष्टि से अतिक्रमण करते हैं। इसके बारे में भी हमें मिल-बैठ कर कुछ सोचना चाहिए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल, ऐसा नहीं है कि वह जो चाहेंगे, वह अमल में आएगा। वह निर्देश तो दे देंगे, मगर जो निर्देश अमल में नहीं आ सकता है, ऐसे निर्देश का उपयोग क्या है? इसलिए मैं मानता हूं कि इस विषय से संबंधित जो संस्थाएं हैं, सरकारें हैं, उन्हें मिल-बैठ कर इस चुनौती का सामना करने के लिए एक एक्शन-प्लान अगर हम बनाते हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पर्यावरण के विषय में एक अत्यंत सजग सरकार के होते हुए इस विषय पर काबू पाना इस चुनौती को मात करना, यह हमारे लिए बिल्कुल कठिन नहीं है। मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Thank you. The next speaker is Shri A. Navaneethakrishnan; you have got seven minutes.

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN (Tamil Nadu): Sir, air pollution in Delhi has now become unmanageable; it has gone out of control. People in Delhi are living in fear. Delhi has become a gas chamber. It is no longer a good place of habitation for human beings. What is the solution? Time and again, the hon. Supreme Court and the National Green Tribunal have been passing orders. Are they sufficient for our citizens? I hope and trust that my friend, Shri Derek O'Brien, has got statistics about deaths caused by air pollution. I hope he has got a reliable data with him. The constitutional right to life free from pollution has not been guaranteed by our administration though the same has been guaranteed in our Constitution. Permit me to read Article 48A of the Constitution — 'protection and improvement of environment and safeguarding of forests and wildlife'. "The State shall endeavour to protect and improve the environment and to safeguard the

[Shri A. Navaneethakrishnan]

forests and wildlife of the country." I want to repeat the words "The State shall endeavour to protect and improve the environment..." Though it is given under chapter "Directive Principles of State Policy", thanks to our Supreme Court judgement, it is an enforceable right. If our environmental rights are violated, we can move the Supreme Court, we can move the NGT or we can move the High Court and get it enforced. So, thanks for the intervention made by hon. Supreme Court. What are the causes of this air pollution? The major sources are fuel wood and biomass burning, fuel adulteration, vehicular emission and traffic congestion, large-scale grass residual burning in agricultural fields in autumn and winter months. These are the major sources of smog, smoke and air pollution. Also, 2016 Environment Performance Index ranked India 141 out of 180 countries. Now, the constitutional right is enforceable. Our Government is taking all steps to prevent air pollution. Now, the latest scheme is 12-Point Draft Plan which is formulated to combat air pollution in Delhi. It is also in place. But there is no guarantee that Delhi will be free from air pollution because every year we are purchasing more number of cars, we are roaming in individual vehicles, we are driving and travelling in individual cars and are not using public transport system. Fortunately, our hon. Prime Minister while inaugurating the Metro requested and advised the people to make use of public transport system. How far it will be accepted and followed is not known. The Constitution contemplates an enforceable constitutional right with regard to environment. Our Government is taking steps but Delhi is becoming a gas chamber. So, what is to be done? My suggestion is that we must have self-restraint. We should not use our own vehicles; we must make use of public transport. We cannot control the agriculturists of Punjab, Haryana and Rajasthan not to resort to grass residuals burning or stubble burning because they have got their own problems. So, unnecessarily, they don't do it. I think they are justified in doing it. Unless alternative method is available to them, why should they not resort to this? So, for their means of livelihood, they have to do it. To save Delhi, subject to correction and approval by this House, the Session may be shifted to southern part of our nation so that our northern friends can come to South India and enjoy food and climate which is free from pollution. So, I welcome all the northern friends to South India and have a good, peaceful and effective Session. We can hold the Session in a place which is most compliant to environment. There is nothing wrong in it. ...*(Interruptions)*... Once our leader, Puratchi Thalaivar M.G. Ramachandran, vehemently argued for shifting our Supreme Court of India to Nagpur or any other central place of India. His point was that poor people cannot be made to travel such a long distance to Delhi and it was rebutted by Mr. Ram Jethmalani.

I attended that meeting. That is only for the sake of convenience that I am making this point. Delhi is not good for inhabitation. Definitely, it cannot be. Everybody is making use of it, polluting it and going back to their native places. So, my humble submission is that any one of the Sessions may be held in Nagpur, Bengaluru, Chennai, Hyderabad, Mumbai, or anywhere else. It is also very useful for national integration. I hope that our Central Government is doing all the work, or, taking all the steps to prevent the air pollution, but changing the venue of Session may also be considered as one of the plans to prevent air pollution in Delhi. Thank you, Sir.

SHRI DEREK O'BRIEN (West Bengal): Sir, I hope you will not look at the time today because this is my maiden speech. It is my maiden speech in my new term.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): You have six minutes.

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, before I begin, I must thank and acknowledge my Party, the Trinamool Congress, and its leader, Mamata Di, to repose the faith to have me elected again and have me back in this House for another term.

Sir, this issue today is very important. There is no doubt about it. Last week, we had a Short Duration Discussion listed on sports. My appeal to the hon. Chairman, through you, Sir, is that next week, we only have one Short Duration Discussion left, and as important as this issue is, of pollution in Delhi, we need to get an issue like farmer distress listed for a Short Duration Discussion in Rajya Sabha. Sports is important. Pollution is important. Jobs are important. The economy is in a mess. That is important. There are so many issues, but one of these other three issues must be taken up. A lot of parties have given notices and this is my humble appeal to the hon. Chairman to take up one of these issues - the jobs, the economy or the farmer distress.

Sir, I have four or five broad numbers just to illustrate the point. Then, I want to talk a little about the causes for pollution and try and get a better understanding about it. Then, I will make two or three suggestions on policy intervention. And, finally, I want to conclude by offering three or four best practices which are being practised by some other States, and maybe the Minister would consider that.

Sir, the first on the broad issues is this, the numbers are very scary, and this is not about this Government or the last Government; this is an ongoing problem for many decades. The population of Ireland or the population of Palestine is equivalent to the people who die of indoor air pollution in the world. Sir, there are basically two broad

[Shri Derek O'Brien]

aspects to pollution, and we have to address both these aspects. One is the indoor air pollution and the other is the outdoor air pollution. To give you these numbers, the outdoor air pollution, in fact, affects less people in the world. About 37 lakh people die of outdoor air pollution. The indoor air pollution is also a huge killer. The second figure, which is alarming, is if you look at the 2013 World Bank Report, and if you look at environmental degradation, they say that 5.7 per cent of GDP is lost because of this poor environmental degradation. Sir, I think that number - 5.7 per cent of GDP - would mean total health contribution and the total education contribution, which would still be under 6 per cent of GDP. That is the second scary number. Sir, out of 37 lakh people in the world who have premature deaths because of COPD and asthma, 25 lakh are Indian. One of the speakers mentioned about the quality of the index. One in two Indians lives in areas that exceed that index, which we call the Indian National Ambient Air Quality Standards. So, these are very scary numbers.

I wish to go into the causes, highlight some of the causes so that we can look for some solutions. The first thing which I want to table in this House is that there are two major causes for indoor pollution. So, the point we am making here is that indoor pollution is a bigger killer than outdoor pollution, and in all the studies which have been done, either through NGOs or through NT, Kanpur, and other groups, there are two killers for indoor pollution. The first big killer is, believe it or not, the mosquito coil. So, where there are mosquitoes — obviously, in the poorer areas, you burn more mosquito coils —COPD cases go up, asthma cases go up. So, mosquito is linked to the coil and that is linked to Asthma, the COPD. This is the first one. The second one, which I know is often used for good reasons for religious purposes and we all use it in Hinduism, Christianity or Sikhism is, what we call in Bangla, the *dhoop,* the *Agarbatti.* That also is a big killer as far as indoor pollution is concerned. So, we need to address these two big issues on indoor pollution.

SHRI JAIRAM RAMESH: *Chulhas* are also a reason.

SHRI DEREK O'BRIEN: Yes, *chulhas.* Let me come now to the issue of outdoor pollution. Sir, there are four causes and we need to address all four. Sir, twelve hundred cars are registered in Delhi every day. If you take 1,200 cars, you can fill the Eden Gardens in Kolkata. So, the first cause is more private transport, as many have suggested. Sir, the second obvious cause for outdoor pollution — and, which I think, the Member from the BJP addressed in his opening remarks, you need to look that way too — is the over-

dependence on coal, and, the faster we move away from that, the better. The third one, Sir, is industrialization and we need to be very, very strict with imposing these rules, whether it is for industrial clusters, whether it is for restaurants, whether it is for thermal power plants. So, these are the issues.

Sir, regarding policy intervention, very quickly, I want to speak about it in three parts. Sir, we need to look at all forms of pollution and not restrict ourselves to one form of pollution. Second, why only Delhi, we need to look at the other metropolitan cities and we also need to look at the smaller towns. For policy intervention, Sir, we need to develop an Air Quality Information System. So, these are policy interventions which will have long-term solutions.

Sir, for good practice, I want to give you three or four examples. Let me give two from my State. Three years ago, we started a scheme, Sabujshree, which simply means that because we need more greenery, every time, a girl child is born in Bengal, a sapling is planted. Now, you will say, why do you discriminate against the boys. It is not that; we hope to include the boys also. So, fifteen lakh saplings are planted every year because it is linked to the birth of a girl child. So, that is one way to increase the greenery.

Sir, the second example from my State is the Green University Bill, which was passed in the Assembly in October-November, 2017, and, the West Bengal Green University has been set up to be a centre for excellence, a centre for learning so that more research can be done in these fields. These are the two examples from the State of Bengal. Sir, I can give you one example from Delhi. Over the last one year, the plantation has increased by about one per cent, maybe 0.9 per cent, because of more efforts towards greenery. During Diwali also, there was also the 'Say No To Crackers' campaign.

Sir, I want to end by sharing with you a statistic which, I think, will make all of us really stand up and take notice, and, this is not from some little village hospital. This is from the All India Institute of Medical Sciences. Please have a look at these figures. In 2005, the number of patients who were admitted into the Respiratory Ward was 5,020. I do not have the figures for 2017 but this figure rose from 5,020 in the year 2005 to 37,000 in the year 2015.

Sir, I would conclude by appealing to you, as I earlier said, to take up another Short-Duration Discussion next week, and, in all humility, also by appealing to the BJP Government that in their efforts to choke the Chief Minister of Delhi — allow him to do his work rather than try and choke him — do not end up choking the children of Delhi. Thank you, Sir.

4.00 P.M.

SHRI PRASANNA ACHARYA (Odisha): Sir, when I was in my area, I was all right. The moment I landed in Delhi, my throat got infected and my doctor says that it is due to severe air pollution in Delhi. Sir, day by day this problem is taking a very alarming situation, particularly in cities like Delhi. This problem is being faced by some other countries and State capitals of some other countries also. My point is, when they have been able to combat the situation, have control over the situation, what is our problem? I will give you one example, Sir. A couple of years ago, China was facing a very critical air pollution situation. It was worse than what we are facing here. They took several measures and improved a lot. Now, we are above China so far as air pollution is concerned. Sir, this is also applicable with respect to other State capitals. We have to consider, we have to study, we have to analyze our problem and see how to solve this problem. Basically, out of many reasons that are attributed for air pollution in Delhi, one big reason is stated to be burning of stubble in Punjab, Haryana and Uttar Pradesh. Sir, this burning of stubble in Punjab, Haryana and Uttar Pradesh is nothing new. Farmers of these States have been doing it since time immemorial. During that time, why was Delhi air not affected and why is it that during the last few years Delhi air is affected and pollution is growing due to stubble burning? So, Sir, that is not the basic reason. If that is happening in Punjab, Haryana and some other neighbouring States, law is there. So, why are those particular States not taking preventive measures? That is number one. Number two, why are farmers of those States not being educated that stubble burning has to be stopped? Sir, vehicular population is increasing in Delhi. The Central Pollution Control Board and the National Environmental Engineering Research Institute, NEERI, have declared that vehicular emission is major contributor to Delhi's air pollution. Sir, vehicular population is estimated at more than 3.4 million, increasing at the growth rate of 7 per cent per annum. It is alarming. People will purchase vehicles; they will use vehicles. You can't stop them. But what about the capitals of other countries? What is happening in New York; what is happening in Washington; what is happening in London? More number of vehicles are running in those cities than in Delhi. How are they able to control it and why are we failing to control it? Sir, in Delhi, construction work is going on on a large scale. Last November, Sir, when the pollution problem was at its peak, the Delhi Administration put a temporary ban on the construction work. But, surprisingly, after only four days, I don't know why, this temporary ban was lifted. A large amount of unauthorized construction is taking place in Delhi and none of the builders are adhering to the norms prescribed by the Pollution Control Board to control pollution. Neither the Central Government nor the Delhi Government is taking any action. That is one of the major reasons why Delhi air is severely polluted.

Sir, coming to industrial pollution, you will be astonished to know Delhi has the highest number of clusters of small-scale industries in India and that contributes to 12 per cent of air pollution. Most of the industries do not strictly follow the measures to check pollution and Pollution Control Board's directives are completely ignored. What is the Administration doing? No checking is done. The Administration does not bother which are the industries which are violating the norms prescribed by the Pollution Control Board. And the unauthorized construction, which is going on rapidly, is rather the major reason for air pollution in Delhi. Neither the Central Government is looking at it, nor the Delhi Government is concerned about it, nor the Corporations are concerned about it. ...*(Time-bell rings)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Please conclude.

SHRI PRASANNA ACHARYA: Just one minute, Sir.

Sir, the population of Delhi is going up. That is a trend of urbanization. Every year, more and more number of people, even from villages, are coming to Delhi and trying to settle down. The population is increasing but we are not making elaborate facilities for the growing population. When there will be more people and little facilities, there will be pollution and you cannot check it. This is one of the prime concerns.

This is my last point. We need to have a national air pollution action plan. I would like to know from the Government what their action plan is. There is absolutely no action plan. It is time the Government had a national air pollution action plan. Thank you, Sir.

श्री हरिवंश (बिहार)ः उपसभाध्यक्ष जी, दरअसल इस समस्या की गंभीरता क्या है, वह शुरू में मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा। मेरी दृष्टि में यह समस्या देश की उन एक-दो समस्याओं में से है, जिनके आगे पूरी व्यवस्था, पूरा सिस्टम लाचार दिखता है। हम दिल्ली की समस्या पर, दिल्ली के वायु प्रदूषण पर बात कर रहे हैं, पर यह देश की समस्या है। WHO की 2014 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 20 बड़े शहर, जो polluted हैं, उनमें से भारत के 10 शहर हैं। मेरा सुझाव है कि दिल्ली के साथ-साथ देश के उन शहरों की भी हम चर्चा करें, उनकी भी चिंता करें।

दूसरी बात यह है कि देश के जो सबसे important effective institutions हैं, वे कई बार इस समस्या को हल करने में असहाय क्यों दिखते हैं? कल यानी 27 दिसम्बर को मैंने इसी संदर्भ में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का एक फैसला यानी ' Graded Response Action Plan' देखा। इसके पहले भी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इस पर काम करता रहा है। इसके पहले Supreme Court mandated Environment Pollution Control Authority है। खुद सुप्रीम कोर्ट इसको कई बार इस सवाल पर गंभीरता से देखता रहा है। सेन्ट्रल पल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, लोक सभा तथा राज्य सभा की पर्यावरण मामलों की स्थायी समिति है। दिल्ली में प्रदूषण का जो स्रोत माना जा रहा है, वह पंजाब और हरियाणा

[श्री हरिवंश]

के किसान के द्वारा पराली जलाने को माना जा रहा है। दोनों राज्यों ने इसके लिए कानूनन प्रतिबंधित किया है कि अगर वहां किसान खेतों में फसल काट कर ऐसे छोड़ेंगे, तो हम उन पर दंड लगाएंगे। इसके लिए कहीं दो एकड़ पर 2,500 का दंड है और कहीं बड़े इलाके में 15,000 रुपए का दंड है। पर, ये बैन्स और फाइन्स भी ineffective हो रहे हैं। कल एक अच्छी खबर आई है कि प्रधान मंत्री जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नेतृत्व में हाई लेवल टास्क फोर्स का गठन हुआ है, Air Action Plan - Abatement of Air Pollution in the Delhi NCR'. मेरा इसमें सिर्फ एक सुझाव है कि इसमें दिल्ली की जगह पूरे देश को रखा जाए कि हम वहां कैसे साफ हवा दे सकें।

सर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमें उन कारणों की तलाश करनी चाहिए, जिनकी वजह से यह स्थिति बनी है। मूल कारण यह है, मैं गांधी को स्मरण करते हुए पुनः कहना चाहूंगा कि हमने प्रकृति के साथ जीना छोड़ दिया। गांधी जी ने कहा था कि प्रकृति सबकी न्यूनतम आवश्यकता पूरी करती है, लोगों का लोभ पूरा नहीं करती। आज नीतिश कुमार पूरे राज्य में, बिहार में और देश के अलग हिस्सों में घूमतू हुए लोगों को याद दिलाते हैं कि अगर हम सचमुच चाहते हैं कि प्रकृति के सानिध्य में रहें, इन चीज़ों से बचें, तो हम गांधी की उस बात की ओर लौटें। सर, आप देखिए कि इसका असर क्या हुआ।

इस देश में Prof. J.K. Galbraith, जो अमेरिका के राजदूत रहे, हमारे आदरणीय जयराम रमेश जी को बहुत अच्छी तरह पता होगा, उन्होंने *The Affluent Society* नामक किताब लिखी। उन्होंने उसमें लिखा कि अगर हम विज्ञापनों के माध्यम से समाज बनाएंगे, जो विज्ञापनों को देख कर हर आदमी के अंदर यह आकांक्षा होगी कि हमारा जीवन उतना समृद्ध, उतना बेहतर और उतना काल्पनिक हो। अगर हम उपभोक्तावादी समाज बनाएंगे, बाजार को हावी न होने देंगे, तो हम किधर ले जाएंगे? सर, आज हालत यह है कि हमने उस आर्थिक दर्शन के तहत अपने विकास का ढांचा बनाया है। हम पहाड़ों, नदियों, जंगलों, इन सबको खत्म कर रहे हैं।

सर, मैं आपको झारखंड के बारे में एक अनुभव बता सकता हूं, क्योंकि मैं यहां आने के पहले एक पत्रकार था। हमने 14 सालों का सर्वे कराया। 16 बड़े पहाड़, जिनको प्रकृति ने दिया था, जो 8-10 करोड़ वर्ष पुराने थे, जिनके बारे में प्रोफेसर बीरबल साहनी ने कहा कि ये *fossils* हैं, इनको सुरक्षा करके बचा कर रखो, वे सारे कट गए, खत्म हो गए। सारे कानून के रहते हुए, सारी चीज़ें रहते हुए, हमने पहाड़ का पहाड़ काट दिया और खत्म कर दिया। नदियां खत्म हो गईं। आज बिहार में बिहार सरकार ने कदम उठाया कि नदियों से जो बालू निकाल करके माफियाज़ खड़े हो रहे हैं, उन पर कैसे कार्रवाई हो। हमने नदियों को खत्म कर दिया, हमने जंगल खत्म कर दिए। अब बाढ़, भूकम्प और तूफान तो हमारे जीवन का हिस्से हो गए हैं, इसलिए हमारी जो राजनीतिक सोच है हर दल की, वह इस तरफ लौटे कि हम लोगों के बीच जाकर कहें कि greed और need के बीच फर्क करें, पर यह शुरूआत ऊपर से हो।

आज भारत में बहुत unequal society हो गई है, धनी लोग और धनी, गरीब लोग और गरीब ...(**समय की घंटी**)... सर, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): आप अपनी बात समाप्त कीजिए, आपका समय खत्म हो चुका है।

श्री हरिवंश: सर, हम इस अर्बनाइजेशन के दौर को रोकें। कारों की भीड़ की बात हो रही है, दो पहिया वहानों की बात हो रही है, हर जगह ट्रैफिक जाम की बात हो रही है। अगर हम उन चीज़ों को रोकना चाहते हैं, तो सचमुच हमें संकल्प लेना पड़ेगा। अभी दिवाली के अवसर पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला दिया। ऐसे फैसलों का हमें आगे बढ़कर स्वागत करना चाहिए ताकि देश में पटाखों का चलन बंद हो, दूसरी चीज़ें बंद हों और मनुष्य का अस्तित्व बना रहे। अगर नई जेनरेशन के लिए हम अच्छा समाज छोड़कर जाएंगे, तभी हम अच्छे कहे जाएंगे। दरअसल आज दो जीवन दृष्टियों के बीच संघर्ष है। गांधी जी की जीवन दृष्टि से जो हमारा पुराना समाज रहा है, आज भी अगर हम आदिवासियों के बीच जाएं, जिस सान्निध्य में वे आज रहते हैं, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। दूसरे पश्चिम का उपभोक्तावादी समाज है, जहां निरंतर लोग अधिक-से-अधिक उपभोग में आनंद पाना चाहते हैं। उसे लेकर अगर हम आगे चलेंगे तो हमारे लिए इस समस्या का निदान पाना मुश्किल होगा। मैंने हाल ही में consumerism पर एक पुस्तक पढ़ी, मैं लेखक का नाम भूल रहा हूं लेकिन वह बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे Penguim Books ने छापा है और लगभग एक हजार पन्नों की वह पुस्तक है। उसमें कहा गया है कि आज दुनिया के जो कथित बड़े विकसित देश हैं, यहां यह हो रहा है कि एक-एक आदमी अपने जीवन में कितने-कितने products खरीदता है, कोई अपने उपभोग के लिए 8 हजार का, 10 हजार का अलग-अलग तरह का सामान खरीदता है - कपड़े, जूते आदि - लेकिन उनमें से कितना उपभोग कर पाता है - बहुत मामूली। बाकी चीज़ें रखी रह जाती हैं। अगर भारत के समाज को हम उसी रास्ते पर ले जाना चाहते हैं तो इस समस्या से देश को नहीं बचा पाएंगे। हमें गांधी जी के रास्ते पर लौटना होगा। मेरा आपसे यही आग्रह है कि गांधी जी के रास्ते पर चलकर ही हम समाज को बचा पाएंगे, धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Now, Shri C.P. Narayanan; you have four minutes.

SHRI C.P. NARAYANAN (Kerala): Sir, on the basis of my experience as a Member of the Standing Committee on Science and Technology, Environment and Forests, I would say that we have been reviewing the situation in Delhi for the last three years and we have found certain things. Four major factors are there. One is construction; another is transport; third is city waste; and fourth, as many others have said, is the burning of stubble in neighbouring States.

Regarding burning of stubble, I have to point out one additional point which was mentioned by the experts. It is that the city of Delhi has got a unique feature. On three sides, there are ridges and when this polluted air comes from Haryana and Punjab over here during the beginning of winter, it has heavy particles and during winter, the wind flow is also very poor. Because of that, these particles are suspended for days together.

[Shri C.P. Narayanan]

That is why, if you look at the last so many years, November-December is the worst period in Delhi and not other months. So, we have to note this. We have to find a solution for this. That is one.

Regarding construction also, there are methods. In various other cities, not done in India but in other countries, there are methods to prevent debris and powdered particles flowing into the air in other areas. This can be prevented. Only thing is that people involved in construction have to spend some more money and the Government has to insist on that.

Third is regarding transport. The Government is taking various measures but still one thing is that we have got diesel vehicles. They cause more pollution than the vehicles running on petrol. There are technical reasons for that. So, these have to be controlled. I am not saying that it is not being done, but it has to be done on a much bigger scale because as my predecessors have said, every year, the number of vehicles plying in Delhi is increasing. Not only Delhi vehicles but also vehicles coming from other parts of the country passing through Delhi, particularly heavy vehicles, all of them have their contribution in increasing the pollution in Delhi. So, these have to be controlled. During the discussion on the NCR Bill and in this discussion also, it has been mentioned that there is lack of coordination between the Central Government and the Delhi Government. We can say various things but we are a democratic country. We have to find a solution for that. We should not stand on party basis. My knowledge is that this issue concerns about 19 million people, who are staying here and about one million or two million people pass through Delhi every day. They are being affected by lack of coordination between, I would say, three elements, that is, the Central Government, the State Government and the local governments. There has to be a better coordination among these.

Fourth point is that people have to play a major role. We have to educate people. I read that in many places there is no separation of waste at the source. The organic waste has to be separated from the other waste. That has to be taken away daily. This has to be properly treated every day. This pattern has to be there. This is not there. So, in all these things, people have to be brought into the figure. They have to be educated. They are to be made a part and parcel of this. Starting from school children to very old people, all these people have to be made a part and parcel of this. In this, the three governments - the Central Government, State Government and the local governments have to play a major role. In this, we, the political party leaders and the administrators as well as the

experts, have to play a y much bigger role. What Delhi is suffering is lack of coordination between these various elements and lack of bringing people into play on all these things. I would request that on the basis of this discussion, the Central Government and the State Government should take more initiatives in this matter. Thank you.

श्री वीर सिंह (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे दिल्ली में वायु प्रदूषण अत्यधिक बढ़ने संबंधी अल्पकालिक चर्चा पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

महोदय, दिल्ली-एनसीआर देश का दिल है। देश की राजधानी नई दिल्ली, जो देश का दिल कहलाता है, जब वही ठीक और स्वस्थ नहीं रहेगा, तो पूरे देश का क्या हाल होगा? आज यह बहुत ही चिन्ता का विषय है कि दिल्ली व एनसीआर में वायु प्रदूषण अत्यधिक बढ़ा है, जिसके कारण लोगों को श्वास लेना मुश्किल हो गया है और तमाम तरह की बीमानियाँ जन्म ले रही हैं। दिल्ली में मृत्यु-दर बढ़ी है। इसको रोकने के लिए उपाय करना अति आवश्यक है। वाहनों से निकलने वाला धुआँ, जो वायु प्रदूषण का कारण है, उसमें पहले नवम्बर पर वाहनों से निकलने वाला धुआँ है। दिल्ली में वाहन अत्यधिक बढ़ रहें हैं, इसके लिए मेट्रो और बस जैसे यातायात के साधनों की ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था की जाए, जिससे छोटी गाड़ियाँ रुकें। जब आम जनता उन यातायात के साधनों से ज्यादा सफर करेगी, तो उससे प्रदूषण रुकेगा।

(**उपसभापति महोदय** *पीठासीन हुए)*

दूसरा - औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला धुआँ तथा रसायन। दिल्ली के आसपास और दिल्ली में जो औद्योगिक इकाइयाँ लगी हुई हैं, उनसे जो धुआँ निकलता है, उससे वायु में बहुत प्रदूषण होता है। उससे भी बहुत सारी परेशानियां पैदा हो रही हैं। मेरा सुझाव है कि एनसीआर में जो आद्यौगिक इकाइयाँ लगी हुई हैं, जिनमें भारी मात्रा में धुआँ निकलता है, उन्हें दिल्ली से दूर लगाया जाए। अगर ऐसा कानून पास किया जाए, तो उससे हम वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं।

आणविक संयंत्रों से निकलने वाली गैस व धूल - जो आणविक संयंत्र हैं, उन पर भी पाबंदी लगनी चाहिए और उस ओर भी ध्यान देना चाहिंए। जगल में पेड़-पौधों के जलने से, कोयले के जलने से तथा तेल-शोधन कारखानों आदि से निकलने वाला धुआँ - जैसे मथुरा का तेल शोधन कारखाना है, तो उस रिफायनी से धुआँ निकलता है। यह बार-बार कहा जाता है कि आगरा के ताजमहल का रंग भी फीका पड़ गया है। वहाँ से उसके भट्टे तो हटा दिए गए हैं, किन्तु उसके अंदर कोई ऐसा उपाय नहीं किया गया है कि वहाँ ऐसे संयंत्र लगाए जाएँ, जिनसे उसका धुआँ कम किया जा सके। इसलिए उस ओर भी ध्यान देना चाहिए।

हवा में अवांछित गैसों की उपस्थिति से मनुष्य, पशुओं तथा पक्षियों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इससे दमा, सर्दी, खांसी, अंधापन, श्रव्य का कमजोर होना तथा त्वचा रोगों जैसी बीमारियाँ पैदा होती हैं। लम्बे समय के बाद जननिक विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं और अपनी चरम-सीमा पर ये घातक भी हो सकती हैं। वायु प्रदूषण से सर्दियों में कोहरा छाया रहता है, जिसके

[श्री वीर सिंह]
कारण धुएं तथा मिट्टी के कणों का कोहरे में मिला होना है। इससे प्राकृतिक दृश्यता में भी कमी आती है, इससे आंखों में भी जलन होती है और सांस लेने में कठिनाई होती है। ओज़ोन परत हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक सुरक्षात्मक गैस की परत है, जो हमें सूरज से आने वाली हानिकारक ultraviolet किरणों से बचाती है। वायु प्रदूषण के कारण जीन अपर्रिवतन, अनुवांशकीय तथा त्वचा कैंसर के खतरे बढ़ रहे हैं। वायु प्रदूषण के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ा है, क्योंकि बारिश के पानी में सल्फर डाईआक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि जैसी जहरीली गैसों के घुलने की संभावना बढ़ी है। इससे फसलों, पेड़ों, भवनों तथा ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान पहुंच सकता है। ...(**समय की घंटी**)... महोदय, मैं अब बस एक मिनट लूंगा।

हमारी केन्द्र सरकार ने, माननीय प्रधान मंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान का नारा लगाया है। मेरा सुझाव है कि दिल्ली के अंदर जो सफाई कमी हैं, आज भी वे झाडू से सफाई करते हैं और उससे धूल उड़ती है, जिससे उन लोगों में टी.बी. का रोग बढ़ रहा है। स्वच्छ भारत तब ही होगा जब हम सफाई कर्मियों को अच्छे यंत्र मुहैया कराएंगे। महानगरपालिका और नगरपालिका को हम उनको समुचित सुविधाएं देंगे, जबकि अभी सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है। आज दिल्ली के अंदर सफाई कर्मियों में टी.बी. का रोग इतना बढ़ रहा है, लेकिन उस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। गटर में घुसने के कारण वे लोग वहां जहरीली गैस के कारण मर रहे हैं, उस ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो मेरा निवेदन है कि स्वच्छ भारत तभी होगा जब सफाई कर्मियों की तरफ ध्यान दिया जाएगा। उनको सफाई यंत्र मुहैया कराए जाएं तथा वायु प्रदूषण को रोकने के लिए इस ओर ध्यान दिया जाए। दूसरा, जैसे कि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश जो नजदीक के प्रदेश हैं, जैसा कि कहा गया कि वहां पराली जलाने के कारण वायु प्रदूषण होता है। इस पर न्यायालय का भी आदेश आया है, जिसका अनुपालन होना चाहिए। किन्तु इसके साथ-साथ जो बड़े-बड़े जमींदार हैं, जिनके बड़े-बड़े फार्म हैं, वे गिने-चुने लोग हैं, जो पराली जलाते हैं। वे मात्र मुश्किल से 5 या 10 परसेंट लोग होंगे। उन पर शिकंजा कसा जाएगा तो प्रदूषण अपने आप रुक जाएगा। इसके साथ-साथ जब दीपावली पर पटाखे छोड़े जाते हैं, उससे वायु प्रदूषण काफी मात्रा में फैलता है। इस पर इस बार न्यायालय को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। तो इस पर भी पाबंदी लगाई जाए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Veer Singhji, your time is over. ...*(Interruptions)*...

श्री वीर सिंहः मेरा यही सुझाव है कि हमें इस ओर ध्यान देना चाहिए। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. ...*(Interruptions)*... Please. ...*(Interruptions)*... Okay, it is all right. You have taken five minutes. ...*(Interruptions)*... Please. ...*(Interruptions)*... Okay. ...*(Interruptions)*... No more. ...*(Interruptions)*... All right. ...*(Interruptions)*... बैठिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री वीर सिंहः जो अस्पताल हैं, रेलवे स्टेशन हैं, वहां पर इतनी भीड़ रहती है, अगर हम देखें कि जो आबादी दिल्ली की 20 साल पहले थी, उससे अब दस गुना बढ़ गई है, किन्तु समुचित व्यवस्था शौचालयों की नहीं की गई है। खुले में अभी भी लोग शौच करते हैं तो उसके कारण से वायु में प्रदूषण होता है। तो दिल्ली सरकार को, केन्द्र सरकार को मिल कर के इस ओर ध्यान देना चाहिए। दूसरा, जो ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. That is all. ...*(Interruptions)*... Nothing more will go on record. ...*(Interruptions)*...

श्री वीर सिंहः जो लोग नदी, नालों के किनारों पर बसे हुए हैं और वे मजबूर हैं खुले में शौच करने के लिए, उनके लिए कोई शौचालय नहीं हैं, उनको मकान देना चाहिए, जिससे कि प्रदूषण रुके। तो इस ओर उनको टॉयलेट्स बनाकर देना चाहिए। यह मेरा सुझाव है, इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए दिल्ली को स्वच्छ रखने के लिए और वायु प्रदूषण रोकने के लिए। धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Nothing more will go on record. ...*(Interruptions)*... Now, Shri D. Raja. Mr. Kashyap, डी. राजा जी के बाद हम आपको ...(व्यवधान)..., because Raja is *Raja*. ...*(Interruptions)*...

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Sir, I have some programme also. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: But Mr. Raja has only three minutes. You can take three plus one, four minutes.

SHRI D. RAJA: Thank you, Sir. We are discussing a very serious issue which is a global issue. According to the *Dialectics of Nature,* there should be a balance among land, air, water and people. This balance is disturbed by the greed and profit-seeking by some classes, some forces in the world. Sir, at this point of time, I would like to compliment activists like Sunita Narain and journals like *Down To Earth,* who are trying to create public awareness on these issues - pollution, environment protection, ecological damage, global warming, climate changes, etc. Sir, the point is how we address this issue. I understand my good friend, Shri Harsh Vardhan, is a doctor. Air pollution is a health issue. The damage to human health because of toxins in air should not be under-estimated. There is a study done in Delhi which shows that Indian children are growing with smaller lungs. When they become adults, in fact, their lungs become ten per cent smaller than the normal lungs. It is a serious health issue, and the Government should address it as a health issue. It concerns the future of our own children.

Sir, the second point is that it is not an issue only confining to Delhi. Of course, Delhi is the national capital, the most polluted city, but, air pollution is not an issue

[Shri D. Raja]
of Delhi alone. Almost, all our cities are affected by air pollution. We do not have the monitoring stations of air pollution in all cities. Only a few cities do have the air pollution monitoring stations, and people do not get to know what to do, what not to do, and this is a kind of silence of conspiracy, and we should tell our people, enlighten our people about this.

The third point is that there are five critical areas which actually become source of pollution. Number one is vehicles. These vehicles which are using the trucks, diesel vehicles, as well as the growing numbers of nuggets, this is one critical area, which is the root cause for pollution. Then, combustion in power plants and industries, using dirty fuels, like, petcoke, and F.O.R. Disvariants, coal and biomass. And third one is, garbage burning, both in landfills and other places, where there is no collection, processing and disposal. The fourth one is, dust management. When I say dust management, it means construction sites as well as roads. We fail to really manage the dust. Then, Sir, the fifth one is, the crop residue burning. These are the five broad critical areas which remain to be the source of pollution. I hope, the Minister agrees with me. Then, what should he do now to control the pollution? I think, first of all, we must encourage the public transport, massive augmentation of public transport, which can reduce the private cars and other things. The other issue is, massive move towards clean fuel. By clean fuel, I mean, natural gas, electricity from cleaner sources, and renewable energy. Sir, here, I must point out, and you will appreciate that India is importing petcoke from countries, like, the United States of America. It really causes pollution. In fact, this is making our country as a dustbin of the world, and is adding to our pollution, and the Government will have to reconsider this issue, import of petcoke from countries, like, US. Then, Sir, there are massive efforts to enforce and implement directions for not burning garbage and dust management. Then, finally, massive efforts to subsidize our farmers to improve and promote the technologies that will allow them to re-plough the straws left over on the field to get into the ground once again. This technology is available. How to promote that technology? The Government will have to subsidize our farmers. It is of no use blaming our farmers for burning down their crops or residues of crops. These are suggestions for pollution control. Thank you.

श्री राम कुमार कश्यप (हरियाणा)ः उपसभापति महोदय, आज मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे इस चर्चा में भाग लेने का मौका नहीं मिलेगा। चर्चा में भाग लेने की अनुमति लेने के लिए मैं आपके पास आया था, लेकिन आपने अनुमति नहीं दी थी। मैं आपसे नाराज़ था। अंत में, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं सिर झुकाकर आपका धन्यवाद अदा करता हूं।

श्री उपसभापतिः आप मेरी बात सुमझिए। आपने कोई चिट मेरे हाथ में नहीं देनी है, आपने चिट उधर देनी है।

श्री राम कुमार कश्यपः सर, मैं तो आपके पास भी गया था।

श्री उपसभापतिः मुझे नहीं देनी है।

श्री राम कुमार कश्यपः सर, मैं सिर झुकाकर आपका धन्यवाद अदा करता हूं।

श्री उपसभापतिः नहीं, नहीं।

श्री राम कुमार कश्यपः सर, जहां तक दिल्ली में प्रदूषण की बात है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please don't bow before anybody, including me. You are a person like me and be straight. Actually, the slips should be given to the officials of the Secretariat. That is why I did not accept it. Now you have nine minutes to speak, which is more than the time given to anybody else.

श्री राम कुमार कश्यपः थैंक यू सर। जहां तक दिल्ली में पर्यावरण दूषित होने की बात है, तो आज दिल्ली में पर्यावरण बहुत दूषित हो गया है। यह हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारी सरकार के लिए बहुत चिंता का विषय है और यह एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है। इस प्रदूषण के कारण हर साल दस हजार व्यक्तियों की समय से पहले मृत्यु हो जाती है। यह बहुत ही चिंता का विषय है। इसी प्रदूषण के कारण बीजेपी के एक नेता कैलाश विजयवर्गीय जी के दो साल में सिर के आधे बाल उड़ गए हैं, यह भी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। कोस्टारिका देश के राजदूत दिल्ली में रहने के लिए आए, परन्तु वे प्रदूषण के कारण दिल्ली छोड़कर बेंगलुरु चले गए। यह भी बहुत ही चिंता का विषय है। प्रदूषण के कारण दिल्ली के स्कूलों में बच्चों की छुट्टियां करनी पड़ीं, यह भी चिंता का विषय है। एक स्टडी के अनुसार अगर WHO के एक वर्किंग स्टैंडर्ड को अपना लिया जाए, तो हम हर एक नागरिक की औसत आयु 9 साल बढ़ा सकते हैं। इसलिए यह बहुत ही चिंता का विषय है और सरकार को इसकी तरफ विशेष ध्यान देना होगा।

उपसभापति महोदय, मैं इसके बारे में दो-तीन सुझाव देकर अपनी बात को खत्म करूंगा। आज दिल्ली में जो प्रदूषण हो रहा है, वह हरियाली की कमी के कारण हो रहा है। इसलिए हमें हरियाली की तरफ विशेष ध्यान देना होगा, दिल्ली में पेड़ लगाने होंगे। इसके अलावा एक चिंता और है। दिल्ली में बहुत सारे बंदर हैं, जो एक भी पेड़ को उगने नहीं देते हैं। यह भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इन बंदरों का दिल्ली में बहुत आतंक है। कोई भी व्यक्ति अपने घर के बाहर कपड़ों को सुखा नहीं सकता है, क्योंकि बदर उनको उठा ले जाते हैं। मैं एक दिन सुबह सैर करके आया और मैंने अपने जूते बाहर उतार दिंए। बदर मेरे जूते को उठाकर ले गया और वह जूता मुझे किसी दूसरे एम.पी. के घर में मिला। यह बहुत ही चिंता का विषय है, इसलिए बंदरों के बारे में भी आपको सोचने की जरूरत है। अगर बंदरों की तरफ ध्यान देंगे, तो कुछ पेड़, पौधे बच जाएंगे अन्यथा नये पेड़, पौधे नहीं लग पाएंगे। पेड़ लगाने में सबका सहयोग जरूरी है, इसमें जनता का सहयोग भी बहुत जरूरी है और इसमें सरकार का सहयोग

[श्री राम कुमार कश्यप]

भी बहुत जरूरी है। मैं तो पहले भी कहता रहा हूं और आज भी कह रहा हूं कि हम में से हर एक आदमी को एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए, one man और one tree उनको लगाए। केवल पेड़ ही न लगाए, बल्कि उनको मेंटेन भी करे।

उपसभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि पेड़ तो बहुत लगते हैं, लेकिन उनको आवार पशु बढ़ने नहीं देते हैं। इसलिए इसकी तरफ भी सरकार का विशेष ध्यान देना होगा। माननीय मंत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पानीपत और सोनीपत एनसीआर में आता है और मैं वहां से आता हूं। पानीपत और सोनीपत के बीच में पेड़ लगान के लिए हजारों की संख्या में ट्री गाड्र्स लगवाए गए हैं, परन्तु उनमें एक भी पेड़ नहीं लगाया गया है। यह इन्क्वायरी का विषय है और माननीय मंत्री जी इसकी इन्क्वायरी करवाएं कि इन ट्री गाड्र्स को लगवाने में कितना खर्च आया और इनमें पेड़ क्यों नहीं हैं? एक बात और है, वह यह है कि सड़क चौड़ी हो रही है, उसके बाद इन ट्री गाड्र्स का क्या होगा और ये कहां जाएंगे, इस पर भी सरकार को विचार करना होगा।

उपसभापति महोदय, आज कूड़ा जलाने से भी प्रदूषण बढ़ रहा है। जितने भी संस्थान हैं, दफ्तर हैं, वे अपने कूड़े में आग लगा देते हैं और उसके कारण भी हमारे यहां प्रदूषण बढ़ता है। विशेष रूप से जो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, उन पर हर रोज़ कहीं न कहीं कूड़े में आग लगी होती है और आग को बुझाने के लिए कोई प्रबंध नहीं है। अगर पेड़ों को बचाना है, हरियाली को बढ़ाना है, तो जो आग लगती है, उसको बुझाने के लिए कोई न कोई प्रावधान करना होगा।

उपसभापति महोदय, आज हम दिल्ली की बात कर रहे हैं और जब हम दिल्ली से हरियाणा जाते हैं, बीच में जो करनाल बाईपास है, उसके राइट हैंड पर डेली कूड़ा इकट्ठा कर लिया जाता है और उसमें लगातार आग लगी रहती है, इसको हम कई सालों से देख रहे हैं। वहां पर कूड़े में से धुआं निकल रहा है, जिसके कारण पता नहीं कितनी बीमारियां फैल रही हैं और वह पर्यावरण को दूषित कर रहा है। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि उसकी तरफ भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाए।

सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।

श्री उपसभापतिः धन्यवाद, कश्यप जी। आप बहुत अच्छा बोले।

श्री प्रताप सिंह बाजवा (पंजाब)ः डिप्टी चेयरमैन साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया। यह सारे देश के लिए एक महत्वपूर्ण इश्यू है, जिस पर बोलने के लिए मुझे पार्टी ने मौका दिया है। सर, मुझे आज आजादी के परवाने याद आ रहे हैं, जिन्होंने देश की आजादी से पहले एक सपना देखा था और कहा था,

"सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा,
हम बुलबुले हैं इस की, यह गुलिश्तां हमारा।"

डिप्टी चेयरमैन साहब, हर हिंदुस्तानी, चाहे वह किसी जमात, किसी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, सभी का यह सपना होता है कि हमारा देश सारी दुनिया में एक मजबूत और खूबसूरत देश बने और हर देश का जो सब से important place उस की capital होती है, वह basically ऐसी जगह होती है, जिस से देश की तरक्की के मापदंड देखे जा सकते हैं। दिल्ली हिंदुस्तान का jewel in the crown है, मगर आज मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है जबकि इसी शहर में राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, प्रधान मंत्री, कैबिनेट के मेंबर्स, Members of Parliament, हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान बच्चे सब इकट्ठे रहते हैं और हम elitist club को join करने की बात करते हैं, लेकिन जब अपना खुद का capital ऐसा है कि सही मायने में हमारा सिंर शम से झुक गया जब श्रीलंकन्स हमारे यहां क्रिकेट मैच खेलने आए, तो one day match में वे और हमारे खिलाड़ी मास्क लगाकर खेलते रहे। सर, श्रीलंकन्स ने हिंदुस्तान के उस ग्राउंड पर, जो एक मशहूर क्रिकेट ग्राउंड है, मैच खेलने से इंकार कर दिया। Is it not a national shame, Sir?

हमारे बहुत सारे साथियों ने अपने views यहां रखे हैं और सरकार भी वाकिफ है कि दिल्ली को क्या-क्या जरूरत है। महोदय, मैं उन आंकड़ों में नहीं जाना चाहता, लेकिन यह बात बिल्कुल सही है कि आज दिल्ली एक gas chamber बनकर रह गयी है और जैसा कि मेरे एक साथी ने कहा कि World Health Studies ने यह साबित किया है कि हिंदुस्तान में जो pollution का level चल रहा है, उस से 25 लाख से ज्यादा लोग हर साल दम तोड़ देते हैं। सर, हो सकता है कि इतने लोग तो हिटलर के gas chamber में नहीं मरे होंगे।

सर, मैं पंजाब से ताल्लुक रखता हूं और वहीं से राज्य सभा में पहुंचा हूं। आज किसान आत्महत्या कर रहा है और दूसरी तरफ हमारी Green Tribunal यह कह रही है कि अगर वे अपनी पराली को आग लगाते हैं, तो उन पर केस रजिस्टर कर जेल के अंदर किया जाए। सर, यह कोई रास्ता नहीं है। मेरी मंत्री महोदय से गुजारिश है कि नीति आयोग ने एक ब्यूरोक्रेट की अध्यक्षता में एक कमेटी से स्टडी करवायी और उन्होंने कहा किं पजाब, हरियाणा और यू.पी. के वेस्टर्न पार्ट में साढ़े ग्यारह हजार करोड़ रुपए खर्च आएगा। सर, यह एक बहुत important parameter है। अगर हम यह चीज रोक दें, तो pollution कम-से-कम 100 परसेंट नीचे आ सकता है। सर, हर्ष वर्द्धन जी खुद एक डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा कि अगर पराली को आग न लगे तो 100 परसेंट pollution level नीचे आ जाता। हर्ष वर्द्धन जी, मैं खुद एक किसान हूं और हमारे बहुत से भाई, जो खुद किसान हैं, वे जानते हैं कि अगर पराली को आग न लगायी जाए तो 3 से 5 हजार प्रति एकड़ का खर्चा आता है क्योंकि उस के लिए labour लगती है, डीजल लगता है, उसके लिए आपको agricultural implements लेने पड़ते हैं, नयी technology लेनी पड़ती है। यह सब अकेला किसान नहीं कर सकता - न पंजाब का, न हरियाणा का और न Western U.P. का। मेरी गुजारिश है कि ये पैसे कोई ज्यादा पैसे नहीं हैं। आज़ाद साहब, एक तरफ तो हम राफेल जेट की बात कर रहे हैं, हम 1600 करोड़ में एक जेट ले रहे हैं और दूसरी तरफ इस समस्या से जूझ रहे हैं। हमें पाकिस्तान से जंग हुए पचास साल हो गए हैं, पर यह तो कुदरत ही जाने कि यह जंग कब बंद होगी या नहीं होगी। हमारी यह जंग चल रही है। उधर हमारे बच्चों की, बुजुर्गों की जंग चल रही है, इधर हमारी यह कैपिटल रहने के काबिल नहीं है। मेरी यह विनती है, गुजारिश है कि नीति आयोग ने

[श्री प्रताप सिंह बाजवा]

कंपन्सेट करने का यह जो पैरामीटर बनाया है, वह है सौ रुपये पर फी क्विंटल पैडी पर बनाया है। एक किस्म से जैसे आप कहते हैं कि बोनस देने का बनाया है। उन्होंने साथ में यह भी बात कही है कि 70 हजार पंचायतें हैं, जिन्हें हम दस-दस लाख रुपये देंगे। जहाँ यह आग नहीं लगाई जाएगी, वहाँ हम उन्हें कंपन्सेट करेंगे। मेरा कहना है कि सौ रुपये की बजाय instead of paying farmers ₹ 100 per quintal as bonus on paddy, जरूरी है कि आप उसको दो सौ कीजिए और जिस पंचायत को दस लाख देने हैं, उसकी बजाय उसको पाँच लाख दिए जाएं। पैसे भी उतने ही लगेंगे, किसान कंपन्सेट होगा और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं on the floor of this House कि हिंदुस्तान का कोई किसान आग लगाने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके भी बच्चे हैं। आज पंजाब में, हरियाणा में वही हालात हैं, जो दिल्ली में हैं। आज पंजाब में वैसे ही हालात पैदा हुए हैं। वहाँ बीमारियाँ हैं। सर, पंजाब में हमें इस दफा, गवर्नमेंट को स्कूल बंद करने पड़े। यह दिल्ली में भी हुआ, पंजाब में भी हुआ। यह इस स्मॉग की वजह से, पॉल्युशन की वजह से हुआ और अनेकों जानें गईं। सर, इतनी कारों के एक्सिडेंट्स, टैक्टर्स के एक्सिडेंट्स, बाइक्स के एक्सिडेंट्स हो रहे हैं, पर उनकी गिनती की तो इधर किसी ने बात ही नहीं की। मेरी यह गुजारिश है कि ग्यारह या साढ़े ग्यारह करोड़ रुपये ज्यादा नहीं है। जो स्टडी यह साबित करती है, उसके मुताबिक इसके चार बेसिक पैरामीटर्स हैं। आईआईटी कानपुर ने एक स्टडी की, उन्होंने यह बताया कि ये जो चार बेसिक पैरामीटर्स हैं, उनमें नंबर 1 पर है, vehicle pollution in Delhi. It contributes 50 per cent pollution. यह पॉल्युशन का परसेंट चल रहा है। कंस्ट्रक्शन, डस्ट की वजह से पचास परसेंट, दिल्ली का जो म्युनिसिपल वेस्ट है, वह सौ परसेंट और जो स्टबल बर्निंग है, सौ परसेंट इसके साथ भी है। मैं समझता हूं कि यह जो सौ परसेंट की डिग्री है, यह नीचे आ सकती है, अगर हम फार्मर्स को कंपेनसेट करें, इसलिए मैं आपसे यह गुजारिश करना चाहता हूं कि इस लड़ाई में हम सभी गवर्नमेंट के साथ हैं। यह हिंदुस्तानियों की लड़ाई है। यह एक सरकार की लड़ाई नहीं है। यह न आपकी है, न बीजेपी की है, न कांग्रेस की है, न ही किसी और पार्टी की लड़ाई है। आज हमें अपना वातावरण ठीक रखना है।

महोदय, हम बड़े-बड़े देशों की बात कहते हैं। आज की सरकार भी बाहर से इंडस्ट्रियलिस्ट्स को बुला रही है कि, आप आओ और हिंदुस्तान में काम शुरू करो। सर, हिंदुस्तान में आएगा कौन? श्रीलंकन चले गए, अमेरिकन गवर्नमेंट के जो बोइंग इधर आते हैं, उन पर पाबंदी लगा दी है। वेस्टर्न वर्ल्ड में जो टूरिज्म का काम है, उसमें बाकायदा तौर पर एक एडवाइज़री इश्यू कर दी गई कि हिंदुस्तान इन दिनों आने या जाने के काबिल नहीं है। हमारे मंत्री जी से, एन्वायरमेंट के मिनिस्टर साहब से मेरी यह विनम्र विनती है कि आप जो मरज़ी कीजिए, मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को एक नेशनल कैंपेन चलाना चाहिए। हम सारी पार्टियाँ जितना जोर अपने इलेक्शन्स पर लगाती हैं, अगर इसका आधा भी लगा देंगे, तो दिल्ली साफ हो जाएगी। हम जितना जोर propaganda पर लगाते हैं, बाकी कामों पर लगाते हैं, यदि एक national awareness campaign चलाएं, तो अच्छा होगा। जैसे टूरिज्म में, मेरे ख्याल से आपके पास यह डिपार्टमेंट रहा था, इसमें इनक्रेडिबल इंडिया से हिंदुस्तान को बहुत लोगों में, बाहर भी लोगों में पॉप्युलर किया था, why don't you start with some kind of

national campaign under the name of Incredible Delhi? दिल्ली के लिए 40, 50 हजार करोड़ रुपये खर्चना कोई मुश्किल काम नहीं है, मगर इसके लिए गवर्नमेंट का मन होना चाहिए। आप आप से कहेंगे, आप वाले लेफ्टिनेंट गवर्नर से कहेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर होम मिनिस्टर से कहेंगे, या हम आपसे कहेंगे, आप हमें कहेंगे, ऐसे तो बिल्कुल काम नहीं चलेगा। अब जरूरी यह है कि as a national awareness campaign हम सभी इकट्ठे हों और सारी दुनिया को यह साबित करके दिखाएं कि हिंदुस्तान को खूबसूरत करने के लिए, दिल्ली को खूबसूरत करने के लिए हम अपने सारे सियासी मतभेद भूलकर देश के लिए और अपनी कैपिटल के लिए एकजुट हैं। मैं इतना ही कहता हूं और हर्ष वर्धन जी, मेरी गुजारिश है कि आप फार्मर्स को कंपन्सेट करो। अगर नहीं करोगे, तो अगले साल फिर यही होगा। आप केसेज़ के साथ, डराने के साथ जितनी मरज़ी कोशिश कर लीजिए, लेकिन ये जो हमारे किसान हैं, ये रुकने वाले नहीं हैं। इनको तो प्यार से मनाइए और कंपन्सेशन दीजिए। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं...। आज पंजाब में भी, हरियाणा में भी, दिल्ली में भी बच्चे पढ़-लिख चुके हैं, कोई किसी को आग नहीं लगाने देगा, आप उनको फाइनेन्शियली कंपनसेशन दे दीजिए। मैं ज्यादा न कहते हुए, डिप्टी चेयरमैन साहब, आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि कृपा कीजिए। आपने थोड़े से बाजू जो अंदर रखे हुए हैं, उनको बाहर निकालिए, क्योंकि इससे ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं बन सकेगा, मेरे वश की बात नहीं है। यह बैठने का तरीका कुछ ऐसा है, उसमें यह होता है कि दोनों हाथ रख लिए कि भाई, मेरे वश की तो बात नहीं, जितना मर्जी बोलते रहो। मैं साथ वाले कश्यप साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ, in a lighter vein, कि अगर कोई बंदर आगे से भी जूता उठा कर ले जाए, तो यह भी ध्यान रखना कि किसी गलत घर में लेने मत चले जाना। यह भी एक बड़ी खतरनाक चीज होती है। तो मैं इतना ही कहते हुए आपका बहुत-बहुत मशकूर हूँ और थैंक्स करना चाहता हूं।

डा. सत्यनारायण जटिया (मध्य प्रदेश): माननीय उपसभापति जी, दिल्ली में प्रदूषण की परेशानियों से किस तरह से निजात पायी जाए, जिससे लोगों के जनजीवन, स्वास्थ्य पर और रोजमर्रा के कामों पर उसका असर न पड़े, यह विषय दिल्ली को लेकर है, परन्तु यह हमारे देश और दुनिया में भी लागू होता है। इन सर्दियों में अखबारों में समाचार छपे कि स्मॉग चैम्बर में दिल्ली तब्दील हुई, 469 तक वायु गुणवत्ता का इंडेक्स पहुंच गया। यह कोई एक दिन में हुआ होगा, ऐसा नहीं है। मैं दिल्ली में 1980 से हूँ, सातवीं लोक सभा से चुन कर आता रहा हूँ। मैंने दिल्ली को बहुत स्वच्छ देखा है, अच्छा देखा है, पार्लियामेंट के आसपास के पर्यावरण को भी अच्छा देखा है। समय के साथ-साथ यह प्रदूषण बढ़ता गया है। इसके रोकथाम के उपाय हमें ज्यादा तेजी से करने होंगे, क्योंकि यह एक मर्ज है। कहीं ऐसा न हो कि हमने दवा की और मर्ज़ बढ़ता जाए। इसके पर्याप्त उपाय करने होंगे। डा. हर्ष वर्धनजी बैठे हैं, निश्चित रूप से ये स्वास्थ्य के बारे में और दिल्ली के बारे में ज्यादा जानते हैं। मैं यह कह सकता हूं कि यह बात जो दिल्ली की है, यह सारे देश की है। इस काम को करने के लिए हमने बहुत सारे उपाय भी किए हैं। यह पर्यावरण का स्तर जो दिल्ली का है, जैसा कहा गया था कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु की गुणवत्ता का स्तर एक बार फिर सीवियर, यानी बहुत गंभीर हो गया है। दिल्ली का अधिकतम एक्यूआई 469, जबकि गाजियाबाद और नोएडा का एक्यूआई अधिकतम 500 स्तर का

[डा. सत्यनारायण जटिया]

रिकॉर्ड किया गया। पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण ने भी दिल्ली और एनसीआर के सभी राज्यों को सतर्क कर देने के निर्देश दिए थे। तो यह बात फॉग से अलग है। फॉग तो होता ही रहता है, जब सर्दी के दिनों में ठंड हो जाती है। इसमें नियंत्रण करने के लिए हम उपाय भी करते हैं। उससे रेलगाड़ियों की रफ्तार रुक जाती है, हवाई जहाजों का उतरना-चढ़ना प्रभावित हो जाता है, इन सारी बातों का हमें अंदाज है, लेकिन जब डस्ट पार्टिकल्स, जिनका आकार बहुत छोटा, न्यून होता है, वे उसमें मिल जाते हैं और धुएं के कण, जो छोटे होते हैं, उसमें मिल जाते हैं और ये जितने ज्यादा बढ़ते जाते हैं, उतना खतरा बढ़ जाता है, तो इसको कैसे कम किया जाए, इस पर उपाय करने की जरूरत है। इसलिए इससे बचाव के हम क्या-क्या उपाय कर सकते हैं? यह राज्य सरकार का मामला होगा, केन्द्र सरकार का मामला होगा, लेकिन यह आदमी की जिंदगी का भी मामला है। हम आदमी को कैसे स्वस्थ और सुरक्षित रख सकते हैं, इसके लिए हमें प्रभावी उपाय करने की आवश्यकता है। इसके लिए बिजली घरों से निकलने वाले धुएं, जैसा हम जानते हैं कि कोयले के बिजली घर से जो धुआं निकलता है, उसकी जो गैस निकलती है, कारखानों से जो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन निकलती है, उससे निकलने वाली गैसेस फेफड़ों को खराब करती है, जिससे बड़ा नुकसान हो जाता है। इनमें एसेडिक कैरेक्टर भी होता है, जिनसे गैसेज़ की भी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। ये सारी बातें स्वास्थ्य से संबंधित भी हैं और दिल्ली का स्वास्थ्य अच्छा रहे, यह जरूरी है। इसके लिए सब प्रकार से उपाय करने चाहिए।

हमने प्रदूषण का स्तर मापने के उपाय भी किए हैं। हमारी दिल्ली में भी इसको लागू करने के लिए काफी प्रयास किए गए हैं। इस संबंध में विदेशों में भी काफी उपाय किए जाते रहे हैं। उन उपायों के अंतर्गत निश्चित रूप से हमने जितने उपाय किए हैं, हमने देखा कि जो स्टेशंस बनाए जाते हैं, जिनसे हम इसका मापन करते हैं, इनको और बढ़ाने की आवश्यकता है। लेजर लाइट के माध्यम से भी इसको नियंत्रित करने के उपाय किए जाते हैं। इस तरह से इसकी जाँच करने के उपाय करने की आवश्यकता है। जाँच तो हम सब प्रकार की कर रहे हैं, किन्तु इन जाँचों से हमें क्या लाभ मिलने वाला है, इस पर ध्यान देना होगा। इसका उपचार कैसे किया जाए? हमारे यहाँ NGT है, वह हमेशा सलाह देता रहता है कि यह करना चाहिए, वह करना चाहिए। इसको लागू करने के लिए जो उपाय करने चाहिए, उसके बिना उसके फैसले लागू नहीं होने के कारण वे अप्रभावी हो जाते हैं। हमारा पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रक प्राधिकरण भी है, वह समय-समय पर हमें चेतावनी देता रहता है, बात बताता रहता है। फिर Graded Response Action Plan है, जिसके तहत क्या उपाय करने चाहिए, यह बताया गया है, जैसे Even and Odd, इस प्रकार से गाड़ियां चलानी चाहिए, गाड़ियों को कम करना चाहिए। अब चाहिए तो सभी कुछ, परन्तु यह होगा कैसे, इसके बारे में यदि सब मिल कर बात करें, तो अच्छा होगा।

अभी एक सुझाव आया था कि इसमें लोगों को साझीदार बनाना चाहिए। Public participation is a must. किस तरह से हम लोगों को इसके बारे में जागरूक कर सकें, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। इसलिए जैसे हमने देश में स्वच्छता अभियान चलाया है, जिसके कारण आज आदमी कहीं भी कचड़ा फेंकने के बारे में सोचना है, उसी प्रकार से हमें पर्यावरण के बारे में भी जागरूकता अभियान चलाने की

आवश्यकता है। यदि कहीं ज्यादा प्रदूषण हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए हमें उपाय करने चाहिए। कानून बने हुए हैं, किन्तु उनका प्रभावी उपयोग नहीं हो पाता है। जहाँ जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है और ध्वनि प्रदूषण होता है, उसके लिए सारे नियम हैं, कानून हैं, परन्तु इनको प्रभावी रूप से लागू करने के लिए हमारी जो एजेंसीज़ हैं, उनके और प्रभावी होने की आवश्यकता है। इसीलिए इन सारे कामों को करने के लिए हम इस तरह से काम करना चाहेंगे। जैसे मैंने कहा था कि हमारे यहां दिल्ली में 38 Air Quality Monitoring Stations हैं, जबकि लंदन में 115 स्टेशंस बनाए गए हैं। इसलिए जाँच के स्तर पर बात करने के लिए हम और स्टेशंस बना सकते हैं। पुलिस और ट्रैफिक पुलिस भी प्रदूषण नियंत्रण में अपना योगदान दे सकते हैं। प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े हुए जो लोग हैं, वे भी इसके लिए गाड़ियों की जाँच करते रहते हैं कि उनसे ज्यादा प्रदूषण तो नहीं हो रहा है। वे गाड़ियों को 'प्रदूषण मुक्त vehicle' का एक लेवल देकर सर्टिफिकेट देने का काम करते हैं। ये सारी बातें हैं, जिनको ठीक प्रकार से लागू करने की आवश्यकता है। इसलिए यह जो हमारे पर्यावरण का काम है, इसको बहुत प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए हमें विविध प्रकार के उपाय करने होंगे, तब जाकर हमें इस समस्या से निजात मिलेगी।

हम जानते हैं कि यह जो सफाई का कचड़ा है, अब यह काम गांवों में ग्राम पंचायत किया करती हैं, नगरों में नगरपालिकाएँ करती हैं, कार्पोरेशंस किया करते हैं, परन्तु संसाधन के अभाव के कारण जगह-जगह उस कचड़े को जलाने का काम होता है। अब अगर उसे जलाएं नहीं, तो फिर उठाएँ कैसे? जहाँ-जहाँ अच्छी व्यवस्थाएं हैं, वहाँ प्रदूषण कम भी होता है। परन्तु इसको प्रभावी रूप से, सार्वदेशिक रूप से लागू करने के लिए हमें इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य की जिन्दगी बहुत ज्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। मनुष्याणाम् नराणाम् आयुः वर्षम् शतम् परमितम्। 100 वर्ष की आयु हो, ऐसा हमारे यहां कहा गया है। अब सौ वर्ष तक कौन जीता है! इसलिए पर्यावरण की शुद्धि करने के बाद भी हम आश्वस्त हो सकते हैं कि इस प्रकार से हामरी जो longevity है, हमें अपनी जिन्दगी में जितनी उम्र मिली है, उसको हम ठीक प्रकार से बिताने के लिए उपाय कर सकें। वैसे भी इस विषय पर किसी का विरोध नहीं है।

"मुख्तसर सी है यह जिंदगी काम करने के लिए,
वक्त लाते हैं कहाँ से लोग विरोध करने के लिए।"

ऐसे विषयों पर तो किसी का विरोध होना ही नहीं चाहिए। इसलिए हम सब मिल कर इसके लिए उपाय करें, जैसा नरेश जी बोला करते हैं कि हम सब मिल कर करें, तो मिल कर करते हुए कभी तो दिखाई देना चाहिए।

श्री नरेश अग्रवालः हम कहाँ इसका विरोध कर रहे हैं?

डा. सत्यनारायण जटियाः विरोध कोई नहीं करता है, परन्तु करते हैं। विरोध करने के अपने-अपने तरीके हैं। इन सारे कामों को करने के लिए हमें जिस तरह के उपाय करने हैं, उनके लिए हमें प्रयास करना चाहिए।

[डा. सत्यनारायण जटिया]

निश्चित रूप से यहाँ फसल के बारे में कहा गया है। किसान परम्परागत रूप से फसल को जलाता आ रहा है, क्योंकि इसमें उसको ज्यादा परिश्रम नहीं लगता, फिर श्रमिकों की बातें हैं। इस प्रकार की मशीनें ईजाद नहीं हुईं। अब मशीनों से कटाई होती है और डंठल रह जाते हैं। इससे किसान का खर्च बढ़ता है, परेशानी बढ़ती है और इसमें टाइम लगता है। पहले तो दराँती से फसल काटते थे, तो उसे नीचे से भी काटा जा सकता था। जैसे-जैसे आधुनिकीकरण आया है, वैसे-वैसे इन चीज़ों को लेकर परेशानियाँ और भी बढ़ी हैं। इस संबंध में केवल किसान के बारे में किस प्रकार से कहा जा सकता है, गलती केवल उसी की नहीं है। इन सारे विषयों पर विचार करने के लिए सर्वांगीण रूप से उपाय करना चाहिए। वैसे हमारी सरकार ने इसके लिए बहुत सारे उपाय किए भी हैं। हमारे घरों में जो चूल्हा जलता था, उस चूल्हे के कारण भी प्रदूषण होता था और हमारे देश की महिलाओं को, बहनों को बहुत कठिनाई होती थी। 'उज्जवला योजना' के माध्यम से इस सरकार ने तीन करोड़ परिवारों को गैस के चूल्हे और अन्य सहायता देने का काम किया है। लोगों तक सरकारी सहायता और जागरूकता पहुंचाने के इस प्रकार के उपाय हमको निरंतर करने पड़ेंगे, तभी हम इन सारी बातों को कह सकते हैं। जैसा मैंने पहले कहा, इन सारी बातों को पर्यावरण के साथ जोड़ कर देखने और जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है।

महोदय, पावर हाउसेज़ के बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा। अभी-भी हमारे यहां बिजली का जो उत्पादन है, वह कोयले पर या थर्मल पावर स्टेशंस पर ही निर्भर है। हम ऊर्जा को वैकल्पिक रूप से कैसे उत्पन्न कर सकते हैं, यह हमें देखना होगा। अभी भी हमारे यहां बिजली के उत्पादन की 80 प्रतिशत निर्भरता कोयले पर ही है। इसका विकल्प क्या हो सकता है अथवा नवीन ऊर्जाकरण के क्या सूत्र हो सकते हैं, यह समग्र रूप से समाज की प्रगति और सर्वांगीण विकास के साथ जुड़ा हुआ प्रश्न है। इस प्रश्न का समाधान ढूंढ़ने के लिए हमें संयुक्त रूप से प्रयास करने की आवश्यकता है।

अभी गाड़ियों के बारे में कहा गया। जो भी सम्पन्न परिवार हैं, आज उन सबके पास अपनी-अपनी गाड़ियां हैं। गाड़ियां तो हैं, लेकिन जगह कहां हैं? हमने मेट्रो बना ली, फिर भी सड़कों पर गाड़ियों के लिए जगह नहीं है। अगर किसी को अभी रेलवे स्टेशन तक की यात्रा करनी हो, तो वह पहुंच ही नहीं पाएगा, उसको रास्ते में ही कहीं उतरना पड़ेगा और दौड़ कर ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। इससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाले 10 वर्षों में हमारे यहां क्या हाल होगा। अगर किसी को एयरपोर्ट पहुंचना हो, तो कई बार हम ऐसी जगह फंस जाते हैं, जहां से निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इन सारी समस्याओं का हल निकालने के लिए हमें बहुपक्षीय ढंग से सोचना पड़ेगा। जहां-कहीं भी जिस-जिस प्रकार का प्रदूषण हो रहा है, उससे मुक्ति पाने के उपाय हमको निश्चित रूप से ढूंढ़ने होंगे।

इसका एक हल यह है किं हम स्वय प्रदूषण न करें और आत्मनियंत्रण करने का उपाय करें। हमारे यहां कहा गया है - 'तेन त्यक्तेन भुंजीथा' अर्थात् त्यागपूर्वक भोग किया जाना चाहिए, हालांकि यह बहुत आदर्शवादी बात है। हमें त्याग करना है तो करना ही है, लेकिन त्याग हमसे होता नहीं और भोग से हम मुक्त हो नहीं पाते, फिर भी हमारे ग्रथों में जो भी उपदेश दिए गए हैं, कुल मिलाकर वे आज

भी सार्थक हैं। हम न तो स्वयं प्रदूषण करें और न ही प्रदूषण होने दें। हम किसी से जाकर झगड़ा तो नहीं कर सकते कि आप आग मत जलाइए या ध्वनि प्रदूषण मत करिए, लेकिन इसको रोकने का अन्य कोई उपाय नहीं है। प्रदूषण रोकने के कुछ उपाय दिए गए हैं, परन्तु उसमें भी अब प्रदूषण आ चुका है, इसलिए इस मैकेनिज़्म को हमें बार-बार जांचना होगा। जिन लोगों को प्रभावित करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय किए जाते हैं, ऐसे सामर्थ्यवान लोग फिर भी उन सारी बातों को करते रहते हैं, लेकिन हम संभवतः उनको रोकने की सामर्थ्य जुटा नहीं पाते हैं। जैसे अगर किसी का एक्सिडेंट हो जाए, तो आज की तारीख में लोग उसको उठाने में डरते हैं, उसकी सहायता करने में विलम्ब करते हैं, जिससे उसकी जिन्दगी खतरे में पड़ जाती है। इसी प्रकार प्रदूषण को रोकने के लिए और उससे होने वाले खतरों से बचने के लिए हमें खतरा तो मोल लेना ही होगा। जब तक हम कतरा-कतरा खतरा नहीं उठाते हैं, थोड़े-थोड़े खतरे नहीं उठाते हैं, तब तक हम इससे मुक्ति नहीं पा सकते हैं। इससे मुक्ति पाने के लिए संकल्प की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी और सरकार इसके लिए सकारात्मक उपाय करे ताकि दिल्ली ही नहीं पूरे देश को प्रदूषण से मुक्त किया जा सके। इस काम में इनको सफलता मिले, इसके लिए मैं शुभकामना करता हूं, साथ ही अपना वक्तव्य भी यहीं समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you Jatiyaji. Shrimati Kanimozhi. You have three plus one, four minutes. ...*(Interruptions)*...

AN HON. MEMBER: One bonus!

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY (West Bengal): Lady Member should get extra time.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We should show some more consideration. But they are equal to everybody. I treat every Lady Member as equal to...

SHRIMATI KANIMOZHI (Tamil Nadu): Sir, after we get 33 per cent, and then we may bring it to 50 per cent, you can treat us equally.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: But I said, I treat equally. ...*(Interruptions)*... I support 50 per cent. No problem. I support. Let the Bill come.

SHRIMATI KANIMOZHI: The Government has to bring the Bill. They are not bringing it. Sir, you should ask the Government.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Government should hear it. The Government is not listening. The Parliamentary Affairs Minister has to listen to what the hon. Member has said. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI KANIMOZHI: The Women's Reservation Bill. ...*(Interruptions)*...

5.00 P.M.

SHRI LA. GANESAN (Tamil Nadu): They were with the Congress Party and they...

SHRIMATI KANIMOZHI: No, we brought it in the Rajya Sabha and it was passed.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It was passed in the Rajya Sabha. ...*(Interruptions)*... Okay. Now you start.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It was passed in the Rajya Sabha. Okay. Now you may start, Shrimati Kanimozhi.

SHRIMATI KANIMOZHI: Sir, every winter we all experience this horror of air pollution in Delhi and it concerns all of us. There was a time when our parents and grandparents could drink water from the taps and from the rivers and lakes. Today, we cannot even think of walking around without a water bottle bought in shops and now, in Delhi, we cannot go out without masks for a walk. I really hope that a day will not come when our children or grandchildren will have to carry air tanks in their bags and go to schools. We have to do something about this before that day comes. Delhi has a celebrity status because it is the Capital of the country and it grabs the media's attention and everybody's attention very easily. But this problem is not there just in Delhi. We have to understand that there are many other cities in India which are more affected by air pollution, like Ennore, Alandur, Thoothukudi, Gumimdipoondi, Kodungaiyur and specially SIPCOT in Cuddalore, in Tamil Nadu, because of industrial pollution. I would like to quote an incident. When an environmentalist-group brought children from Cuddalore to Chennai, the children were surprised, rather shocked, because the air smelt very pleasant and different. They were used to smelling the dirty, polluted air in Cuddalore. So, this is the environment in which our children grow up in many cities. Places like Raigarh and Korba in Chhattisgarh are neither monitored nor regulated adequately. They had more days of very bad air quality than Delhi.

Sir, the Supreme Court banned crackers just before Diwali this year in Delhi, but we did not witness any improvement in air quality after that. There are much larger and important factors such as industries which are close to the cities, and continuous negligence to adopt mitigating efforts to reduce emissions. These are very important. The law requires that in places where air quality is already beyond permissible levels, no activities that increase air pollution burden should be allowed, but in industrial clusters and places with a concentration of power plants, this requirement is always given a goby.

We should also understand that in these areas, generally it is the marginalized communities living there that suffer the most.

Sir, in December, 2015, the Ministry of Power revised the emission norms and gave a two year-time period to thermal power plants to adhere to the rules. These rules aimed to bind all thermal power plants to install three technologies before 7th December, 2017 – Electrostatic Precipitators, ESPs, to control particulate matter, Flue gas de-sulpharisation for Sulphur Oxides and modification of burner designs for lower Nitrogen Oxide emissions. There is no indication that thermal power plants have implemented these technological interventions as required.

Sir, I would like to ask the hon. Minister, through you, as to how many power plants have already implemented these norms. It is also quite shocking to know that instead of enforcing new emission standards for coal-based thermal power plants, the Union Environment Ministry and Power Ministry recently took a stand in the Supreme Court seeking a five year-extension of the deadline to meet these standards. The move may now allow over 300 such plants across the country, including those in the National Capital Region, to continue to emit toxic Sulphur Dioxide and Oxides of Nitrogen without any obligation to adhere to stricter emission norms till December, 2022. Sir, I would take just two more minutes.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You may take one more minute.

SHRIMATI KANIMOZHI: Sir, I would take just two more minutes.

Sir, this is exactly opposed to the Government's policy of 'Clean India'. Many people have talked about crop stubble burning in Punjab and Haryana. Without the Governments giving them other lucrative choices, what choice does the farmer have other than burning it? So, the Government has to intervene and support them and give them other choices. Today, with the improved technology, there are other ways to dispose of this. I think the Government rather than just banning it and moving away from the problem should intervene and help the farmers to solve this issue. Sir, we have to start thinking about cleaner and greener technologies, renewable energy and you have to scale back coal-fired industries, and promote viable public transport facilities which is very, very important. We keep talking about missing our evening walks because of pollution. We have to understand that more than all of us, the affluent classes and the parliamentarians, it is the middle-class people and the deprived sections of the community who are more affected by this air pollution. They are the ones who are more outside and who have to face the

[Shrimati Kanimozhi]

pollution much more than us, and especially the homeless in Delhi are made to suffer much more because of this air pollution. ...*(Time bell rings)*... Sir, one more minute.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have already taken two more minutes.

SHRIMATI KANIMOZHI: We have to understand that this is a huge additional burden on many poor families because their health is affected because of air pollution and they have to spend much more than what they can afford on medicines. One-fifth of the school children in Delhi have lung diseases. ...*(Time bell rings)*... Sir, one more minute. We keep talking about this world as if it only belongs to human beings. That is not true. I think we share this earth with many other species and we have to learn to respect them. Because of pollution, the flora and fauna and so many other animals and micro-organisms get affected and they become endangered and completely destroyed. We have to learn to respect them. We don't understand that we have to protect them because this loss of ours is not actually calculated when we talk about environmental economics. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Very good point. With that, you can conclude. ...*(Interruptions)*... That is a very good point. You can conclude now. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI KANIMOZHI: We have to increase budget allocation for the air quality monitoring to cover all industrial clusters formally covered under Comprehensive Environmental Monitoring Index Study, and a parliamentary Committee to identify air pollution hot spots across the country has to be set up. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Rajeev Shukla, you have only five minutes.

श्री राजीव शुक्ल (महाराष्ट्र)ः सर, उनको 8 मिनट और मुझे सिर्फ पांच मिनट?

श्री उपसभापतिः नहीं, नहीं। पाँच मिनट उनका टाइम है।

SHRI RAJEEV SHUKLA: Thank you, Mr. Deputy Chairman, Sir. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. You have only five minutes.

श्री राजीव शुक्लः पाँच मिनट में क्या होगा? ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. Only five minutes.

श्री राजीव शुक्लः सर, नरेश जी ने अपनी अल्पकालिक चर्चा के दौरान यह जो मुद्दा उठाया है, यह मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ दिल्ली के ही प्रदूषण की बात नहीं है। अगर आपने देखा हो, तो लखनऊ का worst था। दिल्ली से बुरा हाल लखनऊ का था। कानपुर का बुरा हाल था, पटना की भी बुरा हाल था। यह पूरे उत्तर भारत की समस्या बन गया। इसलिए यह सिर्फ दिल्ली का ही प्रदूषण नहीं रह गया। इसका कारण आज तक किसी को पता नहीं है। पहले यह बताया गया कि पराली कारण था। अब इधर पराली तो नहीं है, वह तो जलना बन्द हो गया, तो फिर अब क्यो पॉल्यूशन है? यह किसी की समझ में भी नहीं आ पाया है कि वायु प्रदूषण क्या है, क्यों है? मेरे ख्याल से मंत्री जी को इस पर जवाब देना चाहिए। इससे दुनिया भर में बदनामी है। उसका सबसे बड़ा नुकसान टूरिज्म को है। टूरिज्म को अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है, क्योंकि एडवाइज़री इश्यू हो जाती है कि आपको इंडिया नहीं जाना है, वहाँ पर दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन है। इसलिए उससे हमारा बहुत नुकसान दूसरी तरह से होता है। बहुत से लोग नहीं आते हैं। एयरलाइंस का नुकसान होता है। तमाम trade, commercial activities, उन सब का नुकसान होता है। इसलिए यह बड़ी चिन्ता का विषय है। आप एम्बेसेडर्स से मिलने जाइए, तो वे किस तरह की आलोचना करते हैं! यह जो हाल है, इसके बारे में हमें बहुत आपात स्थिति वाले कदम उठाने चाहिए। उसके लिए मेरे ख्याल से सबसे बड़े चार-पाँच सुझाव मैं मंत्री जी को देना चाहता हूं।

डिप्टी चेयरमैन सर, अभी वित्त मंत्री जी यहाँ पर नहीं हैं। मुझे लगता है कि सब जगहों पर, सारे शहरों में, सबसे ज्यादा pollution vehicles से है। यह हर जगह है, क्योंकि जिस आदमी के घर पर पहले एक कार होती थी, आज चार कारें हो गई हैं। जिस लड़के की तनख्वाह 30,000 रुपये होती है, वह ईएमआई देकर कार खरीद लेता है। पहले जो हम लोग स्कूटर/मोटरसाइकिल पर चलते थे, अब तो स्कूटर/मोटरसाइकिल पर कोई चलता ही नहीं है, डायरेक्ट कार से चलता है। तो इतनी कारों से पॉल्यूशन है। उससे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का हमारा इम्पोर्ट बिल भी बढ़ता जा रहा है। सिंगापुर में जब इस तरह का पॉल्यूशन हुआ था और जब ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम होती थी, तो उन्होंने वहाँ पर कारों के दाम, खास तौर से बड़ी कारों के दाम बहुत बढ़ाये थे। वित्त मंत्री जी को मेरा सुझाव है कि आप छोटे vehicles को तो priority दें और उनको conession दें, लेकिन जो बड़ी-बड़ी कारें हैं, उनके दाम से कम से कम 20 गुना इजाफा करना चाहिए, तब लोग मानेंगे। अगर एक कार 50 लाख रुपए से ऊपर की मिलेगी, तब जाकर लोग चलना शुरू करेंगे। इससे जो पैसा जनरेट हो, उसको आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लगाइए। उससे अच्छी-अच्छी बसें, लोकल ट्रेन, मेट्रो ट्रेन की सुविधा दें। इस प्रकार से उस पैसे को डायवर्ट कीजिए। कारों पर टैक्स कई गुना बढ़ाया जाना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि जो शहर में ट्रकों की आवाजाही है, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था, जिसमें उन्होंने restriction लगा दिया था कि दिल्ली में सिर्फ वही ट्रक आ पाएंगे, जो दिल्ली में माल लाते हैं, those trucks, which just pass through Delhi, should be allowed. उनके लिए बाहर का रूट देना चाहिए। यह पहले कुछ दिन चला, फिर इधर से जाने लगे। जब देखों, सारे ट्रक्स दिल्ली से होकर जाते हैं। रात में हजारों ट्रक्स दिल्ली से होकर जाते हैं और वे सारा पॉल्यूशन यहां छोड़ कर जाते हैं। ट्रकों की आवाजाही के बारे में सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था, that should be implemented.

[श्री राजीव शुक्ल]

तीसरी बात यह है कि पराली के बारे में जो सुझाव दिया था, कैप्टन अमरिन्दर सिंह, पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने मुझे भी इसके बारे में ब्रीफ किया था। इसमें सरकार का मुश्किल से 16 सौ करोड़ रुपए का खर्चा आता। मेरे ख्याल से उसके कारण इससे दोगुना tourism पर नुकसान हो जाता है। अगर पंजाब और हरियाणा के किसानों को 16 सौ करोड़ रुपए का compensation मिल जाए, तो वहां पर यह पराली की समस्या खत्म हो जाए, जिसकी वजह से दिल्ली का air quality index 100 प्वाइंट बढ़ जाता है, वह तुरंत कम हो जाएगा। मेरे ख्याल से वह 16 सौ करोड़ रुपए देने में कोई हर्ज नहीं है। इस संबंध में पंजाब के चीफ मिनिस्टर का जो प्रपोजल था, उसको केन्द्र सरकार ने मना कर दिया। अगर केन्द्र सरकार उसमें मदद करती, तो इससे पराली की समस्या भी हल हो जाती और किसानों की मदद भी हो जाती। मेरा यह कहना है कि सरकार को इस पर भी विचार करना चाहिए।

चौथी बात यह है कि जो 'स्वच्छ मिशन भारत' योजना है, उसका बहुत पैसा इकट्ठा होता है। समोसा खाने जाइए, चाय पीने जाइए, रेस्टारेंट में खाना खाने जाइए, सब जगह स्वच्छ भारत शुल्क लगता जाता है, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल कहां हो रहा है, यह पता नहीं है। 'स्वच्छ मिशन भारत' योजना के तहत आने वाला पैसा कहां लग रहा है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। मेरा यह कहना है कि इस पैसे को डायवर्ट करके इन सब चीज़ों पर लगाया जाए। इससे सीवेज़ प्लांट लगाया जाए, ग्रीन बेल्ट बनायी जाए, नदियों की सफाई की जाए। जो जगह-जगह सफाई की जाए, उसको दिखाया जाए। अभी तो पता चला कि उसका पच्चीस परसेंट पैसे का पता ही नहीं कि वह कहां चला गया, जिसके बारे में मीडिया कमेंट ले रहा है।

पांचवीं चीज़ concentration of population है। यह बड़ी चीज़ है कि गांव के लोग शहरों में आ रहे हैं। इससे शहरों की आबादी बढ़ती जा रही है। अगर शहरों की आबादी इस तरह से बढ़ती चली जाए, तो स्वाभाविक है कि उसकी वजह से पॉल्यूशन हो। इसके लिए एक ही तरीका है कि या तो आप शहर को expand कीजिए, लेकिन मुम्बई तो expand नहीं हो सकता है। दिल्ली सेटेलाइट टाउन्स में नए ऑफिस खोलने की इजाजत ही मत दीजिए, वह ग्रेटर नोएडा में जाकर खोले, गुरुग्राम के आगे जाकर खोले या फरीदाबाद के आगे जाकर खोलो। अगर आप इस तरह से expand कर दीजिएगा, तो उससे जब population spread हो जाएगी, तो उससे जो सब शहरों में concentration बढ़ा था, चाहे वह लखनऊ हो, चाहे कानपुर हो, चाहे पटना हो, चाहे मुम्बई हो, चाहे दिल्ली हो, वह थोड़ा सा expand होगा और उससे लोगों को आसानी रहेगी।

महोदय, गांवों में सुविधाएं बढ़ानी चाहिए, जैसे पंजाब में है। ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे, लेकिन उनका चंडीगढ़ में कभी मकान ही नहीं रहा। जब मैं उनके पास जाता था, तो एक दिन मैंने उनसे इसके बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि बेटे, जरूरत क्या है, जब गांव में सड़क है, गांव में बिजली आ रही है, गांव में टीवी देख लेते हैं, गांव में घर मे कूलर लगा है, एसी भी लगा है, तो शहर में जाकर क्यों रहूं? यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश के गांवों में ये सुविधाएं नहीं हैं कि गांव में एसी भी चल रहा हो, टीवी भी गांव में देख रहे हैं। अगर हम गांवों में इस तरह का infrastructure create कर दें, तो इससे गांवों से शहरों की

ओर पलायन बंद हो जाएगा और इन सब चीज़ों से लोगों के लिए रोजगार की सुविधाएं भी बढ़ जाएंगी। गांवों का विकास सिर्फ रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से नहीं हो सकता है, क्योंकि यह बड़ा विषय है। 1970 में प्लानिंग कमिशन में इंदिरा जी का नोट है कि environment पर long-term prospective होना चाहिए। यह सिर्फ हर्ष वर्धन जी की मिनिस्ट्री का मामला नहीं है, इसको सबको मिल कर करना होगा। अगर सारे मंत्रालय मिल कर इसको करेंगे, तभी यह काम हो सकता है। अगर आप इस भरोसे रहें कि इसको एनजीटी कर लेगा, तो एनजीटी तो आज की तारीख में पुलिस इंस्पेक्टर है। They are only playing the role of policing the environment and nothing else. इसलिए यह रोक दें, वह रोक दें, इन सबसे कुछ नहीं होने वाला है, there has to be a long perspective, as suggested by Mrs. Gandhi in 1970 to the Planning Commission. मुझे लगता है कि इस तरह से बना कर, कई मंत्रालयों को मिलाकर, मैंने ये जो 5-6 सुझाव दिए हैं, अगर उन पर अमल किया जाए, तो हम निश्चित रूप से पर्यावरण की समस्या से मुकाबला कर सकेंगे। आपने मुझे जितना समय दिया था, मेरा भाषण उसी में समाप्त हो गया, धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you very much. Now, Shri V. Vijayasai Reddy. You have three plus one, that is, four minutes.

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, will Mr. Javadekar also speak?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You don't induce him. ...*(Interruptions)*... Mr. Javadekar, he wants you also to speak.

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री प्रकाश जावडेकर): सर, आज सभी लोग positive suggestion दे रहे हैं, कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, अगर कोई विरोध करे, तो मैं बोलूं।

SHRI V. VIJAYASAI REDDY (Andhra Pradesh): Mr. Deputy Chairman, Sir, please set the time to zero.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, you have four minutes. Don't worry.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Mr. Deputy Chairman, Sir, i thank you for giving me the opportunity to participate in this important discussion. The pollution in Delhi hitherto is a recurring problem. If we do not take scientific, concrete and stern measures, it may become a perennial problem, and, if we leave this issue after discussing here in this House without taking any remedial measures, probably, this problem would continue forever. Therefore, this problem has to be addressed by the Government of India.

Sir, why this problem has to be addressed immediately is because it is impacting the lives of the human beings, and, as Kanimozhi Madam pointed out, it is also impacting the lives of other living beings. Sir, the problem is growing exponentially, and, it is impacting

[Shri V. Vijayasai Reddy]
the children and elders who are suffering from respiratory diseases like asthma, pulmonary diseases, heart diseases and various other diseases.

Sir, there are four reasons for pollution. As other Members have also pointed out, first is, vehicular pollution; second is burning of stubble, and, the third is particulate matter that is emanated by the industries, particularly, the thermal units which are located here in Delhi, that is, the electricity manufacturing units. I am not targeting any company but one such company, to which the Government of India has issued instructions very recently to stop the production, for the time being, is Badarpur Power Plant. Sir, in fact, these power plants located in Delhi supply only eight per cent of the total requirement of Delhi whereas they contribute to eighty to ninety per cent of pollution. Therefore, Government of India should see that as far as energy manufacturing companies, particularly, thermal units, are concerned, pollution has to be controlled.

Sir, the second issue is burning of stubble. The rice in Punjab is grown in about 3.2 million hectares of land, which produces about 20 million tonnes of paddy straw. Similarly, in Haryana, Punjab and Uttar Pradesh, after the paddy, within 20 to 30 days, the farmers have to switch over to wheat, and, therefore, they have only 30 days' time to clear this straw, the residual waste, or, somehow, they will have to dispose it off. Sir, the transportation of this residual waste, the residual straw, involves a cost to the extent of ₹ 3,000/- per acre. Instead of spending the amount of ₹ 3,000/- per acre, the farmers burn it in the farms, in the paddy fields. So, this problem has to be addressed and the farmers have to be suitably compensated. The Government should provide the machinery to cut the residual paddy waste and spread it in the paddy fields so that it becomes organic manure for the next crop or so.

There is a solution which is available, Sir. The Punjab Agricultural University developed some technologies, namely, balers and happy seeders. Happy seeders is a machine, which can be provided to the farmers at subsided costs so that it can chop and cut the residual waste, which can then be spread over the farms so that it becomes organic manure for the next crop. ...*(Time-bell rings)*... One more minute, Sir.

Secondly, Sir, this problem has to be addressed psychologically also. The mindset of the farmers has to be changed. You will have to persuade them, the Government has to persuade them so that the farmers change their mindset and adopt scientific measures. Sir, Punjab requires about 15,000 such machines which I have suggested, Haryana requires about 12,000 machines and U.P. requires nearly 20,000 machines. I would like to know

from the Minister whether the Government has any plans to subsidize and supply these machines to the farmers so that this problem of burning of stubble can be addressed.

I would like to draw the attention of the hon. Minister to the final point which is a very important point. ...*(Time bell rings)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. You please conclude.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Just one issue, Sir. The Government is imposing GST at the rate of 18 per cent on air purifiers. I would like to know from you whether you have any plans to reduce this 18 per cent to another slab — the next slab available is zero per cent — so that it will be made available to all those who are interested in reducing the pollution level.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is a good suggestion.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: If you permit, I have one more point.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: With a good point, you conclude. That is good. This is the best suggestion. So, now you conclude.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Thank you very much, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Why don't you ask the Government to do it rather than asking whether they will do it?

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Okay, Sir. I demand the hon. Minister to implement it. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shrimati Chhaya Verma. Take only three minutes.

श्रीमती छाया वर्मा (छत्तीसगढ़): बहुत-बहुत धन्यवाद, सर। मैं कोई भूमिका नहीं बाँधूंगी, सीधे विषय पर बात करूँगी। मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं लगा कि प्रदूषण के कारण दिल्ली में स्कूलों को बन्द किया गया। मैं छत्तीसगढ़ के रायपुर से आती हूं और मैंने समाचार-पत्र में पढ़ा था कि रायपुर पूरे विश्व में प्रदूषण के मामले में तीसरे नम्बर पर है। वहाँ पर सड़क चौड़ीकरण और रेल लाइन बिछाने के लिए बहुत सारे वृक्षों को काट दिया गया। वहां जंगल कट गए और हाथी, भालू, बंदर आदि जंगली जानवर जंगल से बाहर आकर गाँवों में उत्पात मचा रहे हैं, गाँवों के घरों को तोड़ रहे हैं। हम कहते हैं - "वृक्ष धरा का भूषण है, वह दूर करे प्रदूषण है।" पेड़ लगाना चाहिए, लेकिन मैं यह कह सकती हूं कि वहां की सरकार प्रदूषण को बढ़ावा दे रही है। वे सारे जंगल को काट रहे हैं। रायपुर इतना अधिक प्रदूषित शहर हो गया है कि हर दूसरा व्यक्ति स्कीन डिजीज़ से प्रभावित है और हर तीसरा व्यक्ति खाँसी से प्रभावित है। वह इतना प्रदूषित शहर हो गया है कि वहाँ पर कैंसर की बीमारी बहुत ज्यादा हो

[श्रीमती छाया वर्मा]

गई है और खाँसी वहाँ की एक आम समस्या हो गई है। आज के समय में हॉस्पिटल मशरूम की तरह उग आए हैं और उन हॉस्पिटल्स का ई-वेस्ट, हॉस्पिटल का जो प्लास्टिक और वेस्ट होता है, वह पूरी तरह से वातावरण को प्रदूषित कर रहा है। ओज़ोन की परत इतनी ज्यादा कमजोर हो गई है कि उसका छेद बढ़ता जा रहा है और उसके कारण बारिश अनबैलेंस्ड हो गई है। जब पानी गिरना चाहिए, जिस समय किसानों को पानी की आवश्यकता होती है, उस समय पानी नहीं गिरता और गरमी में बारिश होती है। वहाँ का पूरा मौसम, पूरा वातावरण अनबैलेंस्ड हो गया है। "बेमौसम बरसातें होतीं, धरा तृषित रहती सावन में।" सावन में पानी नहीं गिरता और प्रदूषण इतना अधिक हो गया है कि दूसरे मौसम में बारिश होती है।

आदरणीय उपसभापति महोदय, मैं यह बताना चाहूंगी कि अब तो रायपुर का मौसम ऐसा हो गया है कि जब कोई महिला गर्भवती होती है, तो वह प्रदूषित हवा को अपनी सांस में लेती है और जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, वे अपंग और बीमारी लिए हुए पैदा हो रहे हैं। ऐसे समय में स्वास्थ्य विभाग और हमारे मंत्री महोदय को स्पष्ट नीति बनानी होगी, मानव की रक्षा के लिए नीति बनानी होगी और सभी को मिलकर यह नीति बनानी होगी। अभी सत्यनारायण जटिया जी बोल रहे थे। वे कह रहे थे कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए "उज्ज्वला योजना" के तहत गैस कनेक्शन का उपयोग किया गया है, लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि आपने "उज्ज्वला योजना" के तहत गैस कनेक्शंस तो बाँट दिए, लेकिन उसकी कीमत 400 रुपये से बढ़ाकर 800 रुपये कर दी। हमारी बहनों ने उस चूल्हे और सिलेण्डर को अलमारी में सजाकर रख दिया है, उसका उपयोग कहीं नहीं हो रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि आप स्पष्ट नीति बनाएँ और पर्यावरण की रक्षा करें, तभी मानव सही मायने में जीवित रह सकेगा और मानव की रक्षा हो सकेगी। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री नीरज शेखर (उत्तर प्रदेश)ः महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने मुझे समय दिया। ...**(व्यवधान)**... मैं आभार इसलिए व्यक्त कर रहा हूं क्योंकि मेरा समय नहीं था। बोलना मेरा अधिकार है, लेकिन आज उपसभापति महोदय ने मुझे समय दिया है, इसलिए मैं उनका आभार व्यक्त कर रहा हूं।

यह जो वायु प्रदूषण का विषय उठा, मुझे याद है दो-ढाई साल पहले क्योंकि हम लोग सदन में बात नहीं करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कहा कि मैंने अपने पोते को देखा कि वह सुबह मास्क लगाकर जा रहा था। दुर्भाग्य की बात है कि हम लोगों ने इस पर डिस्कशन नहीं किया, जब सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने अपने पोते को देखा तब यह बात कही। हमारे देश में 25 लाख से ज्यादा लोग प्रदूषण से मरते हैं, तब हम लोगों ने यह बात कभी नहीं उठाई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने जब अपने पोते को देखा तब यह समस्या उठती है। इस देश में गरीब मरता रहे, हम लोग उस पर कभी बात ही नहीं करते हैं। जज ने अपने पोते को देखा, उसने हम लोगों को ऑर्डर दिया, एन.जी.टी. को ऑर्डर दिया कि आप काम करिए, प्रदूषण दूर होना चाहिए। आज एन.जी.टी. क्या कर रही है? अपने ऐसे ऑर्डर दे देती है जिसको लागू नहीं किया जा सकता। किसानों को पांच हजार रुपए का मुआवजा,

किसानों को जेल में डाल दीजिए। किसान कहां तक भुगते? क्या किसानों ने आज अपने खेत जलाने शुरू किए हैं? किसान हमेशा अपने खेत जलाता था, तब तो प्रदूषण नहीं होता था। मैं दिल्ली में पैदा हुआ हूं, मैं जिंदगी भर दिल्ली में रहा हूं। पिछले दस साल से मैं यह देख रहा हूं कि यह समस्या हो रही है। जब बचपन में मुझे खांसी होती थी तो दो-तीन दिन में ठीक हो जाती थी। आज मेरी बेटी को खांसी है, पिछले दस दिनों से वह खांस रही है। मुझे ही दुख होता है ज मैं अपनी बेटी को देखता हूं। मुझे दुख होता है, क्योंकि वह रोज खांसती है, उसकी खांसी ठीक नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि आज आप दिल्ली में सांस नहीं ले सकते हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि यह क्यों हो रहा है। सही बोला राजीव शुक्ल जी ने कि हम लोग कारण समझ ही नहीं पा रहे कि क्यों प्रदूषण हो रहा है। मेरा ख्याल है कि जो गाड़ियां बढ़ीं, वह तो है ही, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है दिल्ली व उसके आसपास, जो कंस्ट्रक्शन कम्पनीज़ हैं, हमें उनको समझाना चाहिए कि वे पानी का छिड़काव करते रहें जिससे वहां से धूल न उड़े। मेरे घर के सामने रोज झाड़ू लगती है। हम तो अच्छी जगह रहते हैं, जहां पेड़ इतने सारे हैं। रोज झाड़ू लगती है, धूल उड़ती है, फिर वहीं बैठ जाती है। सफाई के क्या तरीके होने चाहिए, नए तरीके होने चाहिए। दिल्ली में नहीं है तो आप रायपुर की बात कर रही हैं, वहां क्या होगा? मैं इसीलिए कह रहा हूं। हम लोगों को पहले अपनी जो समस्याएं हैं, उनका क्या समाधान हो सकता है, आपस में न लड़ें हम लोग। सब ने यह बात कही, लेकिन अंत में हम लोग राजनीति ले आते हैं। आज हमारे बच्चे सांस नहीं ले पा रहे हैं, क्या वे दिल्ली छोड़कर जाएंगे? चाहे कोई पार्टी हो, राज्य में कोई पार्टी हो या केन्द्र में कोई पार्टी हो, सब को साथ मिलकर किस तरह से इस समस्या से हम लोग समाधान ढूंढ सकते हैं, उसकी जरूरत है। हम लोग आपस में न लड़ें। मैं बस यही आपसे कहना चाहता था। इसलिए मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। नरेश जी चले गए। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और आपका भी आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया, धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you very much. Hon. Minister, we have to pass a Bill also. How much time will you take?

THE MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY; THE MINISTER OF EARTH SCIENCES; AND THE MINISTER OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE (DR. HARSH VARDHAN): Sir, you started with 30 minutes. But I will take 45 minutes.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. Please don't go above 30 minutes.

DR. HARSH VARDHAN: Sir, I will try to be as brief as possible. Sir, so many Members have spoken on it.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You need not reply to the repetitions. Try to complete within 30 minutes.

DR. HARSH VARDHAN: Sir, I will try to be as brief as possible.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is fine.

DR. HARSH VARDHAN: Sir, first of all, let me thank you and all the Members of this august House. Unlike yesterday's discussion on bamboo, today the House has been cool. All of them have spoken very positively about their suggestions. They have had very objective analysis of the whole situation. So, I wish to thank all of them for their valuable suggestions. Because of limitation of time, I may not be able to respond to each one of them although I have noted down everything.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Everybody is supporting you. Then what is the problem?

DR. HARSH VARDHAN: I can only promise this. If there is anything new in whatever has been said here by anyone which is not being done or which has not been ever thought of, we will certainly take that into active consideration. That is number one. Otherwise, in respect of most of the things, when I would tell you what the Government has been doing, you will all appreciate that we are already into most of these things and there is a very, very aggressive and proactive plan of how to handle this unfortunate situation.

Before I get into the nitty-gritty of most of the things, I wish to make a couple of statements. All my life I have worked in the field of health. I started my political career as Health Minister in Delhi and I was the first one who established the first Environmental and Occupational Clinic in Maulana Azad Medical College in the country. I have been pursuing this subject quite regularly and I have found that there is a similarity between health and environment in the sense that like health, environment quality – be it air, water or soil – is determined by the actions of other sectors. That is a very typical similarity. In health also, you deal with patients and you have to treat patients, but others are causing the disease. So, it is like a similar situation in environment also.

The air quality is directly linked to energy, industrial, agricultural, housing and transport policy. These sectors can help both in cleaning up or in demolishing the air quality. Sir, this is also a fact. Then, the role of the Environment Ministry is to monitor both the state of environment and the environmental health, regulate, prescribe norms, enforce standards, advise and also educate public.

Then, I also wish to make a statement that traffic must be reduced and we must ensure a cleaner and greener element to what remains on the roads. We need better

understanding of exposure and health effects, plus further progress in comparing and synthesising data from existing studies, which is there, is needed before drawing any conclusion. A lot of people have spoken about the relationship between pollution and health. Research has concluded that both awareness of the links between air pollution and ill health and an understanding of air quality information are lacking amongst the public. So, we have to act on this front that has not occurred effectively. Another intervention in moving towards a cleaner and healthier environment necessitates behavioural changes by the public which, in turn, requires continued education and optimal communication. We are promoting research and studies to generate data from our own sources to assess the actual impact of air pollution on public health since there may be a design behind highly inflated data that has been proposed by some researchers on morbidity and mortality attributed to air pollution in the country. There are people with half-baked understanding of environmental health making unsubstantiated and unscientific claims to create sensation and scare among public, which may or may not be true. Only science can tell us this. We do understand that clean air protects and our air quality has to be improved to prevent the adverse impact which we do not deny. We wish to further improve monitoring, forecasting and reporting of air quality, using sophisticated models to make it more accurate. In future, use of more individualised exposure measurements holds a great deal and more potential. Then, Sir, we also need to educate and train our budding medical graduates in the discipline of environmental health, which is not presently a part of the medical curriculum. According to ISRO, in three winter months, that is, November to January, the entire Indo-Gangetic plain is not visible through satellite imagery. This means, this entire basin is plagued with air pollution that is contributed by a wide variety of factors including combustion, dust, construction, traffic, etc. Everybody has highlighted all these things. We must ensure regular power supply generated through non-conventional and non-polluting sources so that industry and major power users such as IT, which cannot do without power and have installed big diesel gensets, do not resort to using polluting sources; a transport policy for the entire basin region to augment and promote better use of public transport and reduce dependence on individual methods of contributing to air pollution; and then changes in diesel engine technology and improving the quality of fuel. We have to prepone the public use of electricity-based personal vehicles to cut down the combustion of fossil fuel. Also, we have to strengthen the building of a new urban motorway, urban regeneration programmes to help improve the lives of poorer sections of the community. Since household air pollution caused by crop burning, burning of cow dung cakes, wood and other biomass is a significant contributor to outdoor air pollution,

[Dr. Harsh Vardhan]

the Pradhan Mantri Ujjwala Yojana to provide all households with clean cooking fuels is being speeded up so that this fraction can be brought down. We want the strict observation of dust separation measures by those who create such dust, mostly the construction and real estate developers. There are hundreds of thousands of brick kilns that use polluting fuels. We need to strategize so that they turn to clean fuel use. We must find solution to farmers who are forced to burn crop residues that usually occurs in winters adding to the woes not only in NCR but in the States of U.P., Haryana and Punjab. Then, our Ministry is working on a new model for public participation and public involvement since air pollution or for that matter all sort of pollution management is a monumental challenge that no Government can address alone.

Sir, I just wanted to make some of these statements and then a couple of points more before I come to the original subject because this is something for which, I think, broadly we may agree on some of the things that we could do. To briefly summarize some of the policy initiatives, one country, one fuel, one norm implemented from April, 2017, that is, BS-IV and BS-VI to be implemented from 1st April, 2022 that is the future that we are working on very aggressively. Emission norms for various industrial sectors have been upgraded like for power plants and cement. Real time tracking of emission from seventeen highly polluting industrial sectors through online monitoring devices has already been done.

I am happy that some of the Members raised this issue of indoor air pollution, especially, my dear friend Mr. Derek also mentioned about indoor air pollution. Household and workplace activity is another important source of air pollution exposure. Inside the household, various sources of indoor air pollution include insecticides, pesticides, paints etc.. Cooking using firewood which is basically more confined nowadays in rural areas is another major source of indoor air pollution. I wish to inform this House that Government has already initiated a process of developing guidelines for indoor air pollution. Specific precautionary and preventive measures in line with these guidelines will go a long way in reducing overall air pollution exposure for general public.

Then, a well thought out land use planning is another important mechanism of reducing the exposure to air pollution. Delineation of land use areas as segregation of industrial areas from residential and some of the sensitive areas like schools, colleges, hospitals etc. is the way forward. As a country, India is lagging behind significantly in terms of land use planning. One of the examples is to avoid construction of schools adjacent to major roadways, rail yards and ports.

Then, I wish to comment on another subject, which is also dealt with by me, that is, meteorological factors such as wind speed and direction are usually the strongest determinants of variations in air pollution along with topography and temperature inversions. Therefore, weather reports can be a guide to likely air pollution levels and exposure management. Our Ministry of Earth Sciences and Indian Meteorological Department are already working on improving the quality of forecast and predictions continuously. Then, I wish to give a few small suggestions because earlier also, in reply to a question I mentioned that we have to develop a movement in this country for some good green deeds. Let everyone be doing or concentrating on some good green deeds which help in improving the environment, conserving and preserving the environment. I have a couple of suggestions here to conserve energy at home, at work and everywhere. Look for the energy star label when buying home or office equipment. Many of us have mentioned about car pool. Use public transportation, bike or walk whenever possible. Follow gasoline refueling instructions for efficient vapor recovery. Be careful not to spill fuel and always tighten your gas cap securely. Keep car, boat and other engines properly tuned. Be sure your tyres are properly inflated. Use environmentally safe paints and cleaning products wherever possible. Mulch or compost leaves and yard waste. Choose a cleaner commute - share a ride to work or use public transportation. Combine errands and reduce trips. Walk to errands when possible. Avoid excessive idling of your automobile.

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, I have a request. The hon. Minister can circulate the statement. He can circulate the statement. ...*(Interruptions)*... Let him address some of the issues raised by the Members. ...*(Interruptions)*... This statement, he can circulate. ...*(Interruptions)*...

DR. HARSH VARDHAN: What do you mean by that? ...*(Interruptions)*... If he wants me to circulate it, we will circulate also. ...*(Interruptions)*... It will come in the records, don't worry. ...*(Interruptions)*... It will come in the records.

SHRI JAIRAM RAMESH: You can circulate it to us. ...*(Interruptions)*...

DR. HARSH VARDHAN: What do you mean by that? ...*(Interruptions)*...

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, we do not have to be told to use public transport. The Short Duration Discussion is on pollution in Delhi. Let the hon. Minister address these issues. ...*(Interruptions)*...

DR. HARSH VARDHAN: Sir, I strongly object to this objection. This is a debate or discussion about pollution. Everybody is suggesting. So, can't the Minister talk about something which is good for the people?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have every right to speak in your own way. You have every right. ...*(Interruptions)*... No Member can ask you to speak in a particular way, nor the Chair. You have every right to speak in the way which you think best. Do that.

DR. HARSH VARDHAN: Sir, I thought I should speak on a couple of things.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, you proceed. No problem.

DR. HARSH VARDHAN: Sir, I feel this needs to be developed into a movement and if these people are not willing to be receptive about it, then who is going to be receptive? They represent the whole country. They are supposed to be responsible for developing all this in the society.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Jairam, you have to listen. Mr. Jairam is not listening, that is a problem.

DR. HARSH VARDHAN: Avoid excessive idling of your automobile. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, Mr. Jairam himself is polluting.

DR. HARSH VARDHAN: Conserve electricity and set air conditioners no lower than 24 degree Celsius. Reduce the number of trips you take in your car. Avoid burning leaves, trash, and other materials. And then interventions at the individual level may include the avoidance of exercise or cycling near busy roadways to reduce exposure, and improvements in the ventilation of homes in which biomass fuels are used. On the basis of available forecast, the exposure to pollution can be avoided using the following. Planning strenuous activities when particulate levels are forecast to be lower. Reducing the amount of time spent at vigorous activity. You can also reduce particles indoors by eliminating tobacco smoke and reducing your use of candles, wood-burning stoves and fireplaces. I thought you had mentioned about it.

Sir, then I have to mention about a few international best practices, which I thought may be of help for the people to know that the Mexican Government recently introduced a significant measure aimed to generate 35 per cent of country's energy from renewable sources by 2024. We also have a very ambitious plan of doing 40 per cent by renewable sources.

Then, Mexico built a seven megawatt plant that converts 214 million N3 of landfill gas into electricity which powers the Light Rail Transit System and city street lights at night. The United Kingdom has also implemented some measures in London to take

taxis older than 15 years and private vehicles older than ten years off the roads, build bicycle super highways, which is called the cycle revolution, and introduced 300 hybrid buses. Urban forests and green roofs have also been proposed as strategies for reducing pollution in urban areas. Vegetation removes pollutants in several ways, by absorbing gaseous pollutants through interception of PM by leaves and by breaking down organic compounds such as polycyclic aromatic hydrocarbons.

Sir, I made these statements because I thought these were important and I wanted to put them on record.

I now come to the basic subject. A lot of hon. Members have mentioned this. Probably, they are not aware what the Government has been doing. Some hon. Members suggested that it was only because an hon. Supreme Court Judge had said that his son and his grandson were wearing masks, that the system worked. I think it is not like that. The Government of India is doing its best in terms of what it has to do on all accounts, and in a perfectly scientific manner. I feel what we have done in the last three years is certainly far better than what has ever been done in the past. There is a good news. During the year 2017, the number of 'severe', 'poor' and 'very poor' Air Quality Index days was less than those in 2016, 181 in 2017 as compared to 214 in 2016. Then, the number of 'good', 'moderate' and 'satisfactory' days were greater this year as compared to the last year; 151 in 2017 as against 109 in 2016. This is all happening because there has been a consistent effort on the part of the Government to implement and monitor all types of possible strategies.

A lot of hon. Members have spoken about the Graded Response Action Plan. It is being implemented very strictly, Sir. The Central Pollution Control Board has already made a 42-Point Action Plan, which is being implemented and monitored to such an extent that the Central Pollution Control Board organises meetings every month with all the stakeholders. That is number one. They have started it from the 1st of September this year. Because ours is the national Government, anybody can say, "Why should you be sending your teams?" But because we were worried and bothered, we sent forty teams from the Central Pollution Control Board to various parts of Delhi and, especially, to all those hotspots where pollution levels had been very high; and there, at those hotspots, our teams advised initiatives and, through WhatsApp, immediately sent information to the Delhi Pollution Control Board; later, weekly reports were sent to the Chief Minister of Delhi as also to the L.G. of Delhi. This was started on the 1st of September. Then, people have already mentioned about it. There is a high-level task force which has been

[Dr. Harsh Vardhan]
constituted; it is headed by the Principal Secretary to the Prime Minister. A draft action plan has already been formulated. It has already been put in the public domain. It is a long plan, which has 12 points with all the details, addressing all the concerns that you have raised. May be, in the first week of January, they are going to meet once again after they get all the inputs. Anybody can make these suggestions on the website of the Ministry of Environment. There also, in respect of all those points, they propose to have final time-line for the implementation of the required interventions. Then, I mentioned research, about their relationship between health and air pollution. I may tell you that our Department, with ICMR, and then, of course, with the major institutions, Pulmonary Department in AIIMS, the Paediatrics Department in AIIMS, the Tuberculosis Department, and the Patel Chest Institute, we are doing a scientific study of the situation in Delhi, specially, of establishing the detailed relationship between the pollution and ill-effects of air pollution on health. Then, I wish to highlight....

श्री नीरज शेखरः सर, यह अभी और कितनी देर चलेगा? ...(**व्यवधान**)... मैं सर से पूछ रहा हूं। क्या मैं पूछ भी नहीं सकता?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no; I have already told him.

DR. HARSH VARDHAN: I wish to highlight that ultimately it has been established that dust pollution is a very, very significantly major cause of high level of particulate matter in Delhi, and we have identified it as a priority area of action, and the Ministry is also coming up with detailed guidelines for mitigation of dust pollution.

Then, Sir, I wish to inform everybody that the National Ambient Air Quality Standards emphasized twelve pollutants. Twelve pollutants have already been notified under the Environmental Protection Act, 1986. Hundred and fifteen emission effluent standards for hundred and four different softwares of industries, besides, thirty-two general standards for ambient air have also been notified by the Central Government. Then, the National Air Quality Monitoring Programme has a network of 691 monitoring manual operating stations which are covering three hundred and three cities in twenty-nine States and four Union Territories. In addition to this, we have eighty-six real time – continuous ambient air quality monitoring stations in fifty-seven cities. Delhi has already got ten numbers plus eighteen, and twenty additional stations have been established. There is also an extensive online monitoring of industrial pollution which is being done for seventeen major industries by the Central Pollution Control Board. Then, on the vehicular front, there also, we are proactively working for cleaner and alternate fuels like CNG and LPG,

ethanol blending, universalization of BS4. By 2017, it has already been done. We are going from BS4 to BS6 by April 2020, and the Minister is also trying to advance it further. Then, for the public transport promotion, you know, how aggressively the Government of India is working for strengthening metro system, buses, e-rickshaws, and the Ministry of Transport is very actively working and helping the States for strengthening the Pollution Under Control Certificates Granting Mechanism. Then, we all know that for the first time in the country, our Prime Minister in 2015, launched a National Air Quality Index. It was started with fourteen cities. Now, it is extended to thirty-four cities. You can get your data in your phone. I have already mentioned about the Graded Response Action Plan. Then, the forty-two measures that I mentioned, includes all the relevant issues, like, vehicular emissions, re-suspension of road dust, the other emissions, biomass, municipal solid waste, industrial pollution, and, of course, construction and demolition activities. All these are being notified, advised, and also monitored by us. Sir, many hon. Members mentioned about involvement of children from schools; I wish to inform you that this year, at least three months before Diwali, we started Harit Diwali and Svastha Diwali Campaign. I myself sent emails to two lakh Principals of Delhi and NCR schools. We used to have regular functions with a thousand such children and gave certificates to thousands of children. ...*(Interruptions)*... Also, Sir, we launched Swachh Award under Swachh Bharat Campaign on 15th October where 15,000 children participated at the India Gate. And, Sir, we have seen the result. This year, Diwali was far cleaner and the air quality was far better. ...*(Interruptions)*...

श्री नीरज शेखरः सर, कोई फर्क ही नहीं पड़ा है। दीवाली के पटाखों के प्रदूषण में कोई फर्क नहीं पड़ा है।

श्री उपसभापतिः नीरज जी, आप बैठिए।

DR. HARSH VARDHAN: Please look at the data.

Sir, I have to inform you that every month, the Central Pollution Control Board is holding meetings at the ministerial-level, whether it is me or my colleague in the Ministry or my Secretary or at the Prime Minister's level; we have continuously had at least one dozen meetings. I have got the dates of all of them with me.

Sir, briefly I mentioned that on almost all the fronts the Government of India is actively working. Not only working, Sir, we are also monitoring everything that we are trying to do. Everything is being done in a very transparent manner. You can see everything that is happening.

[Dr. Harsh Vardhan]

Sir, I have a couple of suggestions. It is not because of any political reason. I wish to suggest a couple of things to the Delhi Government; we have seen a number of friends of the Delhi Government in this august House also. So, they can also probably convey. I have personally conveyed to the Chief Minister also. We feel that there are some critical issues. Water sprinkling on an extensive scale has not been taken up despite repeated instructions from our side. I think, this is a very, very critical issue. It appears to be trivial but is a very important one. In fact, we should also try to launch a movement so that at least the people can sprinkle water outside their homes. That is the minimum that somebody can do.

Then, Sir, landfill sites have not been properly maintained. They have become pollution hotspots in Delhi. Instructions given by the Central Pollution Control Board for the landfill sites have not been observed. Then, Sir, solid waste management is not done as per the laid down norms. A large number of instances of littered solid waste and burning of solid waste are seen all over the city. The dust mitigation measures that have been suggested by the Government of India have not been strictly enforced at the construction sites. Also, the State Government has failed in augmenting the mass transit system in Delhi. I think, Nareshji also mentioned about the money of ₹ 800 crore or so. Whether it is ₹ 700 crore or ₹ 800 crore, I don't know what the exact amount is. But, it is widely reported in newspapers and at other places that the environment compensation cess fund, which is about ₹ 700 crore, has not been utilized by the Delhi Government. I think, these are the couple of suggestions that I made.

Then, Sir, I wish to...

श्री विजय गोयलः सर, मेरा निवेदन है कि सदन का समय एक घंटा बढ़ा दिया जाए, क्योंकि अभी एक Resolution और एक बिल पास करना है। ...**(व्यवधान)**... The Repealing and Amending Bill, जैसा तय हुआ था।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We have a consensus already on that. We extend it by one more hour, up to 7.00 p.m. You may proceed now. First of all, we have to take up the Statutory Resolution and then there is the Repealing and Amending Bill. Mr. Minister, please.

DR. HARSH VARDHAN: Sir, I will take a maximum of five more minutes.

6.00 P.M

Shri Rajeev Shukla and some other Members said that probably we don't know what the cause of pollution is. Sir, it is not like that. I will refer to a study and let all the Members know about it. There was a study which was done by IIT, Kanpur. It was the most relevant study on this subject and where they have said that the PM 2.5 levels are at least 4.7 times higher here in the capital and there is a difference in the national ambient air quality in summers and winters. They have said that in winters, the secondary particles contribute 25 to 30 per cent, vehicles contribute 20 to 25 per cent, bio-mass burning contributes 17 to 26 per cent and municipal solid waste burning also contributes 8 to 9 per cent and to a lesser extent soil and road dust and, of course, in summers the particles contribute 10 to 15 per cent, vehicles contribute 6 to 9 per cent, bio-mass burning 7 to 12 per cent, municipal solid waste 8 to 7 per cent and of course, in summers the soil and road dust contribute significantly. That is about 26 to 27 per cent and coal and fly-ash contribute 26 to 37 per cent. Sir, there is a report of the Ministry of Earth Sciences. That is also headed by me. Between 6th and 16th of November, 2017, till November, 6th, PM 2.5 was in the range of 140 to 190 microgram per cubic millimeter. On November, 8th, when this entire crisis was happening, pollution levels peaked to higher levels, there was gulf dust storm which was contributing almost 40 per cent to this and the stubble burning was contributing 25 per cent and the remaining 35 per cent was local. We should also be aware of this fact as to what are the various types of things, not from inside the country, but from outside the country which are actually contributing. Finally, Sir, somebody raised an issue about Diwali. Let me update him about the figures of Diwali this year. Sir, this year, between the last year's Diwali and this year's Diwali, PM 2.5 decreased by 39 per cent, Sulphur decreased by 20 per cent, potassium decreased by 30 per cent, calcium, copper, zinc etc. decreased by 35 to 40 per cent, iron, barium decreased by 50 and then aluminium chloride decreased by ten per cent. This is all scientific; this is all official. So, we should be able to appreciate that if there is a participation and if everybody works, then, ...*(Interruptions)*... Sir, finally, what I wish to say is that these are all interventions, but, ultimately we need to develop a good quality social movement in the society with the involvement of youth also and more particularly, the school children. Educate them about the causes of air pollution and other types of pollution. Promote good green deeds in the society in a big way. All the Members of this august House can pledge that they will help in developing a movement in their respective areas. I am sure that in times of come, with the speed with which we are getting conscious about this fact, by developing new policies and updating ourselves with everyday advancements, I am sure that we should be able to handle this issue of air pollution in a big way. Once again, I thank all the Members for their positive suggestions and for all the objective thinking on this issue. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you very much.

Now, let us take up the Statutory Resolutions. The first one is by Shri Shiv Pratap Shukla.

STATUTORY RESOLUTIONS

Increasing the Rate of Basic Customs Duty on Soyabeans

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SHIV PRATAP SHUKLA): Sir, I move:

"In pursuance of section 8A (1) of the Customs Tariff Act, 1975, read with sub-section (3) of section 7 of the said Act, this House hereby approves of Notification No. 88/2017-Customs, dated 17th November, 2017 [G.S.R.1431 (E), dated 17th November, 2017] which seeks to increase the basic customs duty on Soyabeans, falling under Tariff items 12011000 and 12019000 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 from 30% to 45%."

The question was put and the motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the second Statutory Resolution. Shri Shiv Pratap Shukla.

Increasing in the Rate of Basic Customs Duty on certain goods

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SHIV PRATAP SHUKLA): Sir, I move:

"In pursuance of section 8A (1) of the Customs Tariff Act, 1975, read with sub-section (3) of section 7 of the said Act, this House hereby approves of Notification No.80/2017-Customs, dated 27th October, 2017 [G.S.R.1339 (E) dated 27th October, 2017], which seeks to increase the rate of basic customs duty on the following goods:-

(a) From 10%/15% to 25% on:-

Tariff heading	Description
1	2
5003	Silk waste (including cocoons unsuitable for reeling, yarn waste and garnetted stock).